04 - यादगार हो सकता था संविधान पर चर्चा का सत्र

05 - संगठन, सहकार और समरसता का 'सानंद'

A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 18 दिसंबर, 2024

06 - धार नगर के नव निर्वाचित मंडल अध्यक्ष का भाजपा कार्यालय में...

07 - संसदीय परंपराओं के निर्वहन में मध्यप्रदेश विधानसभा का...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-108 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

चुनावी राजनीति में सॉफ्ट टारगेट क्यों बनती जा रही हैं महिलाएं?

संतोष पाठक

भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में इस तरह की योजनाओं की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि राजनीतिक दल इसे चुनाव जीतने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने लग गए हैं।

भारत की राजनीति में महिलाएं राजनीतिक दलों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बनती जा रही हैं। देश के सभी राजनीतिक दलों को यह लगने लगा है कि महिला मतदाताओं को लुभा कर चुनावी जीत हासिल की जा सकती है। यही वजह है कि एक के बाद एक कई राज्यों में राजनीतिक दलों ने खासकर सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने महिलाओं के खाते में सीधे कैश पहुंचा कर सत्ता में फिर से वापसी करने में कामयाबी हासिल कर ली है।

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के दौरान शिवराज सिंह चौहान, लाड़ली बहना योजना चलाकर अपने आपको पूरे राज्य की महिलाओं के लिए भाई और बच्चों के लिए मामा के रूप में स्थापित कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के नक्शे-कदम पर चलते हुए हाल ही में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति गठबंधन सरकार और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने सत्ता में जोरदार वापसी की है।

राजनीतिक दल चुनावी राजनीति के हिसाब से किस तरह से महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट मान रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ सरकारें अब चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम भेजने की योजना लाते हैं और अगर संभव होता है तो एक-दो क़िस्त भेज भी देते हैं और फिर महिलाओं से यह वादा करते हैं कि अगर वे उनकी पार्टी को चुनाव जीता दें तो फिर से सरकार बनने के बाद वे उस राशि को बढ़ा देंगे। अब इसे महिला सम्मान योजना का नाम दिया जाए या लाड़ली बहना योजना का नाम दिया जाए या फिर कोई और नाम दिया जाए लेकिन सही मायनों में यह एक चुनावी रिश्वत से ज्यादा कुछ नहीं होता है।

हाल ही में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी यही किया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर हर महिला के खाते में एक हजार रुपए भेजने की घोषणा की, हालांकि वे और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दोनों ही इस बात को बखूबी समझते हैं कि चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे जाने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन उस पर भी तुर्रा देखिए कि केजरीवाल ने एक तरह से महिलाओं को चुनावी लालच देते हुए यह भी घोषणा कर दी है कि विधानसभा चुनाव जीतवा दो तो इसे बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस योजना में होने वाले खर्च की राशि को लेकर कई तरह की गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।

भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में इस तरह की योजनाओं की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि राजनीतिक दल इसे चुनाव जीतने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने लग गए हैं। चुनावी शोर, चुनावी वादें और चुनावी जीत की गहमा-गहमी के बीच असली मुद्दे कहीं गौण होते नजर आ रहे हैं।

सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की योजनाएं चुनाव के पहले ही क्यों शुरू की जाती है ? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या 1000, 1500, 2100 या 3000 रुपए की राशि से सभी समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाता है। वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और फ्री नौकरी निहित होती है लेकिन विडंबना देखिए कि सरकारों ने इन मुद्दों पर स्थायी काम करने की बजाय कामचलाऊ हल ढूंढ लिया है।

सरकार और देश के राजनीतिक दल, लोगों को फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और फ्री नौकरी देने से बचने के लिए बाकी हर चीज मुफ्त में देने को तैयार है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि महिला मतदाताओं को ही आगे बढ़कर, नेताओं से यह सवाल पूछना चाहिए कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की हालत इतनी खराब क्यों हैं ? प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की फीस बेतहाशा क्यों बढ़ती जा रही है ? जिस देश में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की कमी है, उस देश में एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च सालाना एक करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैसे हो गया है ? सरकारी अस्पताल में समय पर उचित और फ्री इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है ? नौकरी तक का फॉर्म भरने के लिए बेरोजगार बच्चों से सैकड़ों-हजारों रुपए क्यों लिए जा रहे हैं ? क्योंकि अगर आप जोड़ कर देखेंगी तो ये सभी खर्च मिलाकर आपको महिला सम्मान या लाडली बहना योजना के नाम पर मिलने वाली राशि से कई हजार गुना ज्यादा बैठ जाएगी।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

जयपुर में पीएम मोदी की उपस्थिति में पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के अनुबंध सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए

मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक : मुख्यमंत्री यादव

भोपाल (एजेंसी)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पार्वती- कालीसिंध -चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को 'सुजलाम्-सुफलाम्' बनाएगी। आज यहां पर मध्य प्रदेश राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच जो अनुबंध सहमति पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) हस्ताक्षरित हुआ है, वह सामान्य सहमति पत्र नहीं है, यह आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) पर मध्य प्रदेश राजस्थान और केंद्र सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए गए। इसके पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने चंबल नदी के जल से युक्त कलश के जल को एक बड़े कलश में प्रवाहित किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए कालीसिंध नदी के जल से युक्त कलश के जल और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिए गए पार्वती नदी के जल से युक्त कलश के जल को भी उसी बड़े कलश में प्रवाहित किया।

अटलजी का सपना साकार हुआ

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने नदियों को जोड़ने का विजन (सपना) रखा था और उसके लिए विशेष समिति भी बनाई गई थी। नदियों को जोड़ने की योजना तो बन गई पर उन्हें पूर्व सरकारों ने अनावश्यक रूप से उलझाए रखा। परंतु हमारी सरकार विवाद नहीं- संवाद की, विरोध नहीं- सहयोग की नीति पर कार्य करती है। इसी का परिणाम है कि आज पार्वती- कालीसिंध -चंबल लिंक परियोजना के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। परियोजना के अंतर्गत चंबल व उसकी सहायक नदियों पार्वती, कालीसिंध और चम्बल को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे मध्यप्रदेश और राजस्थान में विकास के नए द्वार खुलेंगे।

राजस्थान और मध्यप्रदेश के चंबल और मालवा क्षेत्र के लिए यह एक अद्वितिय योजना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। मध्यप्रदेश 20 वर्षों के इतंजार और उपेक्षा के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से यह परियोजना पूर्ण हो सकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक युग के भागीरथ की तरह उन्होंने राजस्थान और मध्यप्रदेश को इस परियोजना के माध्यम से जल प्रवाह की सौगात दी है। राजस्थान और मध्यप्रदेश के चंबल और मालवा क्षेत्र के लिए यह एक अद्वितिय योजना है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो अभियान से संपूर्ण पश्चिमी मध्यप्रदेश होगा लाभान्वित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मंगलवार का दिन मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदी जोड़ो अभियान के लिए त्रि-पक्षीय अनुबंध होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश और राजस्थान को 72 हजार करोड़ रुपये की अद्भुत परियोजना की बड़ी सौगात दी जाएगी। इससे मध्यप्रदेश के 13 जिलों में न केवल पीने के पानी की बल्कि सभी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। जल, भगवान की देन है लेकिन जल का सदुपयोग सरकार के माध्यम से समाज के हित में होता है। गत 20 वर्ष से किसी न किसी कारण से राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच होने वाला समझौता टला। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में यह बदलाव का दौर है। इस परियोजना से श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर सहित आगर, इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर इत्यादि संपूर्ण पश्चिमी मध्यप्रदेश में पीने के पानी और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा राजस्थान के ग्राम दादिया (जयपुर) में पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यक्रम केलिये रवाना होने के पहले जारी अपने संदेश में यह बात कही।

परियोजना के लिए 90 प्रतिशत राशि केन्द्र से

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस परियोजना के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि केन्द्र द्वारा स्वयं 90 प्रतिशत की राशि इस परियोजना में मध्यप्रदेश और राजस्थान को मात्र पांच-पांच प्रतिशत ही व्यय करना होगा। इस प्रकार 77 हजार करोड़ की इस परियोजना इस परियोजना में 70 हजार करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा और साढ़े तीन-तीन हजार करोड़ मध्यप्रदेश औरराजस्थान सरकार व्यय करेगी।

परियोजना से श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर सहित आगर, इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर इत्यादि संपूर्ण पश्चिमी मध्यप्रदेश में पीने के पानी और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। परियोजना से प्रदेश के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा। मालवा और चंबल क्षेत्र में 6 लाख 13 हजार 520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 60 वर्ष पुरानी चंबल दाईं मुख्य नहर एवं वितरण-तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से भिंड, मुरैना एवं श्योपुर जिले में कृषकों की मांग अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल, पेयजल और उद्योगों के लिये आरक्षित रहेगा। परियोजना अंतर्गत 21 बांध/बैराज निर्मित किये जाएंगे।

सुप्रभात

आया दौर फ्लैट कल्चर का,
देहरी, आंगन, धूप नदारद।
हर छत पर पानी की टंकी,
ताल, तलैया, कूप नदारद।।
लाज-शरम चंपत आंखों से,
घूँघट वाला रूप नदारद।
पैकिंग वाले चावल, दालें,
डलिया,चलनी, सूप नदारद।।
बढ़ीं गाड़ियां, जगह कम पड़ी,
सड़कों के फुटपाथ नदारद।
लोग हुए मतलबपरस्त सब,
मदद करें वे हाथ नदारद।।
मोबाइल पर चैटिंग चालू,
यार-दोस्त का साथ नदारद।
बाथरूम, शौचालय घर में,
कुआं, पोखरा ताल नदारद।।
लोकतंत्र अब भीड़तंत्र है,
जनता की पहचान नदारद।
कुर्सी पाना राजनीति है,
नेता से ईमान नदारद।।
गूगल विद्यादान कर रहा,
मास्टर का सम्मान नदारद।
धरती के भगवान देखकर, ऊपर
का भगवान नदारद।।

- सूर्यकुमार पांडेय

लोकसभा में स्वीकार हुआ एक देश एक चुनाव बिल

बिल को लेकर हुई वोटिंग, पक्ष में 269, विरोध में 198 वोट पड़े

वोटिंग रिजल्ट पर कांग्रेस बोली- सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में मंगलवार को एक देश, एक चुनाव बिल के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ।बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं।

पर्ची से मतदान होने के बाद पक्ष में वोट बढ़े-12.10 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिड़ला ने बिल पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट डाला। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो पर्ची दे दीजिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को लगे तो वह पर्ची के जरिए भी अपना वोट संशोधित कर सकता है।

- **कांग्रेस बोली- बिल पर सरकार को बहुमत नहीं मिला**- कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि संसद में सरकार को बिल के लिए दो-तिहाई बहुमत (307) चाहिए था, लेकिन सिर्फ 263 वोट मिले।इसके विरोध में 198 वोट पड़े। ये बिल जरूरी बहुमत नहीं जुटा सका है।
- **32 पार्टियां बिल के साथ, 15 ने विरोध जताया**- एक देश-एक चुनाव पर 32 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। इनमें जगन मोहन रेड्डी की बायएसआरसीपी, के चंद्रशेखर राव की (बीआरएस) और पलानीसामी की एआईएडीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। ये तीनों पार्टियां किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं हैं।

व्हिप के बावजूद 20 से अधिक भाजपा सांसद सदन से रहे नदारद, अब पार्टी भेजेगी नोटिस

हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है: अमित शाह

मंगलवार को संसद के उच्च सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कई आरोप लगाए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये हम सभी के लिए संकल्प लेने का समय। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है।

45 कोचिंग सेंटर पर केंद्र सरकार की गिरी गाज

● 61 लाख का जुर्माना, छात्रों को 1.15 करोड़ का रिफंड ● सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों पर अपनाया कड़ा रुख

नईदिल्ली (एजेंसी)। सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ा रुख अपनाया है। 45 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए। 19 संस्थानों पर 61,60,000 रुपये का जुर्माना लगा। यह कार्रवाई छात्रों के हितों की रक्षा के लिए की गई। सीसीपीए ने कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है। भ्रामक विज्ञापन बंद करें। नियमों का पालन करें।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए 45 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा है। 19 कोचिंग संस्थानों पर 61,60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सीसीपीए ने यह कार्रवाई छात्रों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ की है। कई कोचिंग सेंटर झूठे दावे करके छात्रों को लुभाते हैं। सीसीपीए ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर लगातार नजर रख रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने छात्रों को फीस वापसी में मदद की है।

ऐक्शन में सीसीपीए

सीसीपीए 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत स्थापित किया गया है। इसका काम है उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों को रोकना। ये विज्ञापन जनता और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ होते हैं। सीसीपीए का मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करवाना है।

कोचिंग सेंटर्स को भ्रामक विज्ञापन बनाने से रोकने के लिए सीसीपीए ने 13 नवंबर, 2024 को 'कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2024' जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश कोचिंग सेंटर्स को झूठे या भ्रामक दावे/विज्ञापन करने और भ्रामक या अनुचित व्यवहार करने से रोकने के लिए हैं।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन के लिए विभिन्न कोचिंग सेंटर्स को 45 नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने 19 कोचिंग संस्थानों पर 61,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार बंद करने का निर्देश दिया है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 18 °c | न्यूनतम 13°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 18 दिसंबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

शीत लहर से कंपकंपाए कई राज्य

● राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर, नोएडा-गाजियाबाद में 5वीं तक स्कूल बंद

● एमपी-सीजी बॉर्डर पर बिछी बर्फ की चादर...2 डिग्री पहुंचा पारा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में देश के मैदानी इलाकों में तेज सर्दी जारी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर समेत 10 राज्यों में कोल्ड वेव और 13 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है। वहीं एमपी-सीजी बॉर्डर पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी यहां 2 डिग्री पारा पहुँच गया है। राजस्थान के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पहुंच गया। मध्य प्रदेश में 12 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। भोपाल में 53 साल बाद दिसंबर में रात का टेंप्रेचर 3.3 डिग्री पहुंचा। यहां

1971 में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज हुआ था।

इधर दिल्ली में भी दिसंबर में चौथी बार तापमान 5 डिग्री से नीचे गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण और ठंड के चलते 5वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बर्फबारी के बाद जम्मू-कश्मीर में शीतलहर जारी है। श्रीनगर में मंगलवार सुबह पारा माइनस 4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कई जगह फव्वारों का पानी जमने लगा। पेड़-पौधों पर भी ओस जम गई।

राजस्थान - 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट 14 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे

आज भी 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। राज्य में तेज सर्दी से 22 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 24 घंटे में सीकर, झुंझुनूं के एरिया में शीतलहर का जबरदस्त असर रहा। 36 शहरों में तापमान 5डिग्री से नीचे चला गया है।

उत्तर प्रदेश में 31 जिलों में कोहरा, पारा 5 डिग्री, विजिबिलिटी 80 मीटर, बारिश की आशंका

31 जिलों में सुबह से कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 80 मीटर रह गई। मौसम विभाग का कहना है कि आज बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार को यहां का न्यूनतम पारा 5 डिग्री दर्ज किया गया।

संक्षिप्त समाचार

शिवराज ने उठाए आप सरकार पर सवाल

● दिल्ली में किसानों को नहीं मिल रहा लाभकारी योजनाओं का फायदा...

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही कृषि संबंधी विभिन्न लाभकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा। इसके लिए मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली

सरकार की आलोचना की। उन्होंने दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के सवाल का जवाब देते हुए लोकसभा में यह बात कही। सांसद बिधूड़ी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से देशभर में किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं।

प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश मुद्दा

नई दिल्ली (एजेंसी)। वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंचीं, जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो लिखा था। एक दिन पहले ही वे फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थीं। जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद भी हुआ। प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा था- मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, इसे कोई और तय नहीं करेगा, बरसों से चल रही रूढ़वादी पितृसत्ता को मैं नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी, वही पहनूंगी। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ में कहा कि हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं।

संघ प्रमुख भागवत बोले-

अहंकार दूर रखें, नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे, सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी

पुणे (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए नहीं तो वह गड्ढे में गिर सकता है। पुणे में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी है।

संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि हर व्यक्ति में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है, जो समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है, लेकिन अहंकार भी होता है। राष्ट्र की प्रगति केवल सेवा तक सीमित नहीं है। सेवा का उद्देश्य नागरिकों को विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना होना चाहिए।

प्रदेश में शून्य से नीचे आया तापमान, अमरकंटक में जम गई बर्फ... शिमला जैसा था नजारा

शिमला, नैनीताल-जम्मू से भी ठंडा पचमढ़ी, पारा 1.6 डिग्री, भोपाल समेत 20 जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में इस बार जनवरी से भी ठंडा दिसंबर है। भोपाल समेत कई शहरों में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 8 दिन से शीतलहर चल रही है, जो 9वें दिन मंगलवार को भी चलेगी। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर समेत 20 जिलों में कोल्ड वेव यानी, शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। सोमवार-मंगलवार की रात पचमढ़ी, शिमला, नैनीताल-जम्मू से भी ठंडा रहा।

समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा मैकल पहाड़ी के केंद्र बिंदु पर स्थित नर्मदा उद्गम पवित्र नगरी अमरकंटक में वर्ष 2024 की सबसे अत्यधिक ठंड की सुबह 17 दिसंबर मंगलवार को दर्ज हुई। यहां तापमान 0 डिग्री से नीचे आ गया है।

नर्मदा उद्गम स्थल से लेकर कपिलधारा तक पूरे अमरकंटक नगर में मंगलवार की सुबह जमाव भरी ठंड थी। रात में आई तापमान की गिरावट से घास पर ओस पूरी तरह से बर्फ का रूप ले ली थी।

कड़ाके की ठंड की वजह से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में स्कूलों की

टाइमिंग पहले ही बदल दी गई थी, जबकि भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर लगाए गए हैं। सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, मंगलवार के बाद शीतलहर का दौर खत्म होने का अनुमान है और कुछ दिन तक थोड़ी राहत मिल सकती है। मंगलवार को 20 जिलों में शीतलहर चल रही थी। इनमें से 6 जिले- शाजापुर, आगर-मालवा, सीहोर, रायसेन, मंडला और छतरपुर में पेड़-पौधों की पत्तियों पर बर्फ भी जम सकती है।

भोपाल में 4 डिग्री, ग्वालियर-जबलपुर में 5 डिग्री पारा- मध्यप्रदेश में तेज सर्दी का दौर जारी है। सोमवार-मंगलवार की रात में कई शहरों में रात के टेम्प्रेचर में गिरावट दर्ज की गई। इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस वजह से यह शिमला, नैनीताल, जम्मू शहर, कटरा, धर्मशाला, पालमपुर, देहरादून से भी ठंडा रहा। भोपाल में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ग्वालियर-जबलपुर में 5 डिग्री, जबकि इंदौर में 10.6 डिग्री और उज्जैन में 8 डिग्री दर्ज किया गया। पचमढ़ी के अलावा मंडला, उमरिया, नौगांव, राजगढ़, खजुराहो में भी कड़ाके की ठंड रही। मंडला-उमरिया में 3 डिग्री, नौगांव में 3.8 डिग्री, राजगढ़ में 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। टीकमगढ़, रायसेन, रीवा, छिंदवाड़ा, मलाजखंड और सतना में तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा।

भोपाल में टूटा 58 साल का रिकॉर्ड, पारा 3.3 डिग्री रहा- भोपाल में दिसंबर की सर्दी का 58 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 15-16 दिसंबर की रात में टेम्प्रेचर 3.3 डिग्री रहा। अब पारा 0.3 डिग्री लुढ़का तो ओवरऑल रिकॉर्ड टूट जाएगा। कड़ाके की ठंड की वजह से भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों के लिए हीटर लगाए गए हैं।

इन जिलों में आज कड़ाके की ठंड का अलर्ट

- भोपाल में पिछले 8 दिन से शीतलहर चल रही है। 9वें दिन, मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम बना था। कोल्ड वेव का अलर्ट है।
- जबलपुर में शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। मंगलवार को भी कोल्ड वेव जैसा नजारा था।
- शाजापुर, आगर-मालवा, सीहोर, रायसेन, मंडला और छतरपुर में शीतलहर के साथ बर्फ भी जम सकती है।
- राजगढ़, देवास, खंडवा, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल और सिवनी में भी शीतलहर का अलर्ट है।

25 दिसंबर से फिर से तेज ठंड, पूरे जनवरी में पड़ेगी

मौसम विभाग के मुताबिक, क्रिसमस (25 दिसंबर) से प्रदेश में सर्दी का पीक शुरू होगा। विंड चिल फैक्टर (हवा में ज्यादा ठंडक) के कारण 31 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी का दौर पड़ेगा। सर्दी के अंत तक इस पूरे सीजन में कड़ाके की सर्दी वाले दिनों की संख्या 45 तक हो सकती है। इसकी शुरुआत नवंबर से ही हो गई थी। नवंबर में 36 साल बाद ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ी थी।

सरकार जरा सुध लो

भ्रष्टाचार से परेशान शख्स लोटते हुए जनसुनवाई में पहुंचा, कलेक्टर ऑफिस में सब देखते रहे तमाशा

मल्हारगढ़ नगर पालिका पर घटिया निर्माण का आरोप

मंदसौर (नप्र)। कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में मल्हारगढ़ के ज्ञानेश प्रजापति लोटते हुए अपनी समस्या सुनाने पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में मौजूद अधिकारी व कर्मचारियों ने भी उन्हें नहीं उठाया। वे लोटते हुए जनसुनवाई कक्ष तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मल्हारगढ़ नगर परिषद सीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहा।

मल्हारगढ़ के वार्ड 6 के निवासी ज्ञानेश प्रजापति मंगलवार सुबह लगभग 11:30 बजे कलेक्टर कार्यालय में गेट से लोटते हुए जनसुनवाई कक्ष तक पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी भी देखते रहे।

आवेदन देकर जांच की मांग- ज्ञानेश प्रजापति ने कलेक्टर के नाम आवेदन भी दिया है। इसमें नगर परिषद मल्हारगढ़ में चल रहे निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई।

शिकायत में कहा गया कि वार्ड 12 में नाला निर्माण में भ्रष्टाचार, वार्ड क्र. 4 कायाकल्प योजना का सीसी निर्माण में भ्रष्टाचार, वार्ड 5 आंबेडकर मांगलिक भवन के ऊपर डोम निर्माण की जांच की जाए।

नगर परिषद मल्हारगढ़ में वार्ड 12 नाला निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें 8 एमएम का सरिया लगाया गया है। घटिया निर्माण के कारण जगह-जगह से नाला टूटने लगा है। आगे जाकर नाला एक छोटी सी नाली में तब्दील कर दिया गया। इस नाले के अंदर छोटी-छोटी नालियां बनाई गई। नाले का नीचे का फर्श पूरी तरह तड़क गया है। इसमें हो रही बड़ी बड़ी दरारें घटिया निर्माण की कहानी बयां कर रही है।

ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का आरोप

आरोप है कि नगर परिषद के इंजीनियर भी भ्रष्टाचार में शामिल है, जिन्होंने जांच के नाम पर गलत रिपोर्ट बना दी। ठेकेदार और इंजीनियर का कहना है कि कमीशन नगर पंचायत से लेकर जिला अधिकारियों तक बंटता है। कमीशन के चक्कर में इन निर्माण कार्य की विधिवत जांच नहीं हो रही।

आवेदन में लिखा गया है कि शहरी विकास अभिकरण के जिला परियोजना अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। कलेक्टर ने 20 अगस्त 2024 को नाला निर्माण के संबंध में सीएमओ और इंजीनियर को रिकॉर्ड लेकर बुलाया था, लेकिन उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

फरियादी का कहना है कि अगर टेस्ट रिपोर्ट सही है, तो नाला जगह-जगह से टूटने व तड़कने क्यों लगा है? बिल में सरिया 12 एमएम का पास किया गया है। पूरे मामले की जांच होना चाहिए।

संभल में एक और बंद मंदिर मिला

● मस्जिद के पास नए कुएं की खुदाई, कार्तिकेय मंदिर के बगल के मकान का छज्जा तुड़वाया

संभल (एजेंसी)। संभल में 4 दिन में 2 बंद मंदिर मिले हैं। दोनों मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हैं। पहला मंदिर 14 दिसंबर को जामा से डेढ़ किलोमीटर खग्गूसराय में मिला था। दूसरा मंगलवार को हयात नगर के सरायतरीन में मिला। मंदिरों की बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। मंगलवार सुबह जैसे ही मंदिर मिलने की सूचना मिली। पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया- मंदिर काफी समय से बंद था। पहले यहां 30-40 हिंदू परिवार रहते थे, जो 1978 के दंगे के बाद पलायन कर गए। इधर, 4 दिन पहले मिले कार्तिकेश्वर मंदिर से चंद कदम दूरी पर मस्जिद के पास कुआं मिला है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नगर पालिका ने कुएं को बंद करा दिया था। मंगलवार को प्रशासन की टीम ने बंद कुएं को खुदवाना शुरू किया।

- **जामा मस्जिद से करीब डेढ़ किमी दूर मिला नया मंदिर-** संभल में मंगलवार को जो नया मंदिर मिला है किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना प्रशासन को दी थी। इसके बाद अफसर पहुंचे। वहां जानकारी हासिल की। राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची। यह मंदिर, जामा मस्जिद जहां हिंसा में 4 युवक मारे गए थे, वहां से करीब डेढ़ किमी दूर है।
- **विष्णु शंकर बोले- यह मंदिर रस्तोगी समाज का है-** खग्गू सराय निवासी 82 वर्षीय विष्णु शंकर रस्तोगी ने कहा कि यह रस्तोगी समाज का मंदिर था। 1978 के दंगों के बाद 40 से 45 रस्तोगी परिवार के लोग यहां से मंदिर बंद करके चले गए। उसके बाद पूजा पाठ भी बंद हो गई। हम यहां बचपन से रहे है, यहां से लोग दहशत की वजह से चले गए।

प्रियंका के हैंडबैग पर विजयवर्गीय बोले-

यह मुस्लिम तुष्टिकरण, हिंदुओं और ईसाइयों की वकालत का नाटक; देश इनकी हकीकत जानता है

इंदौर (नप्र)। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के हैंडबैग पर मध्यप्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'यह हिंदुओं और इसाइयों की वकालत का नाटक है।'

प्रियंका मंगलवार को संसद में 'बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो' लिखा हुआ हैंडबैग लेकर पहुंची थीं। इसके एक दिन पहले सोमवार को वह संसद में फिलिस्तीन समर्थन वाला हैंडबैग लेकर पहुंची थीं। इस पर विजयवर्गीय का कहना है, 'यह मुस्लिम तुष्टिकरण है। देश इनकी हकीकत जानता है।'

विजयवर्गीय ने एक्स पर लिखा... कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी कल संसद में फिलिस्तीन समर्थक प्रतीकों वाले हैंडबैग के साथ पहुंचीं। वहां उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में बयान

दिया। यह घटना महज संयोग नहीं, एक पुरानी परंपरा की पुनरावृत्ति है, जिसे उनके पूर्वजों ने वर्षों पहले स्थापित किया था। उसी कुटिल राजनीति का दुष्परिणाम देश ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के रूप में भोगा और आज तक उसकी कीमत चुका रहा है।

उन्होंने आगे लिखा- चौतरफा आलोचना और राजनीतिक दबाव के बाद, आज वे संसद में एक नया प्रपंच रचने पहुंचीं। इस बार बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन का झंडा उठाकर। अचानक हिंदुओं और ईसाइयों की वकालत का यह नाटक, उनके दोहरे मापदंड और राजनीतिक अवसरवाद का जीवंत प्रमाण है। अब इसे वैचारिक विचलन कहें या सांप्रदायिक संतुलन साधने का प्रयास, किंतु यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की यह 'हैंडबैग राजनीति' उनकी खोती हुई जमीन पर मरहम लगाने का असफल प्रयास है। ये मुस्लिम तुष्टिकरण है। देश इनकी हकीकत जानता है।

शिवसेना (बीटी) की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग

उद्धव बोले- कांग्रेस सावरकर और भाजपा नेहरू की रट छोड़े

नागपुर (एजेंसी)। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना (बीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। उद्धव ने कहा- कांग्रेस को वीर सावरकर और भाजपा को अब नेहरू की रट नहीं लगानी चाहिए। इन महापुरुषों ने जो किया वह किया, अब आगे भविष्य पर बात करनी चाहिए।

कलेक्टोरेट की सीढ़ियों पर बैठे जनप्रतिनिधि

मीटिंग में अफसरों के नहीं पहुंचने से नाराज; बोले-सीएम से करेंगे शिकायत

भोपाल (नप्र)। मंगलवार भोपाल की फंदा जनपद की साधारण सभा की बैठक में अधिकारियों के न पहुंचने से नाराज अध्यक्ष और सदस्यों ने कलेक्टर ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध जताया, इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत करने की बात कही हैं।

अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने कहा कि अधिकारी मोबाइल भी रिसीव नहीं करते हैं। मंगलवार दोपहर 12 बजे जनपद पंचायत फंदा की साधारण सभा की बैठक रखी गई। अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष राजपूत ने की। सीईओ शिवशंकर पांसे ने एजेंडा रखते हुए बैठक शुरू की। बैठक में सभी जनपद सदस्य उपस्थित थे, लेकिन सिर्फ छह विभाग के अधिकारी ही मौजूद थे।

अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए सीईओ से पूछा कि बैठक में ओर विभागों के अधिकारी क्यों नहीं आए? इस पर सीईओ पांसे ने कहा, सभी को सूचना दी गई थी। जो नहीं आए, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष राजपूत ने बैठक के एजेंडे पर चर्चा करते हुए विभागों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों के नहीं आने पर नाराज जनपद अध्यक्ष और सदस्य कलेक्टर ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठ गए।

पैदल कलेक्टोरेट पहुंच गए अध्यक्ष-सदस्य

बैठक के बाद अध्यक्ष राजपूत और सभी सदस्य पैदल ही कलेक्टोरेट पहुंच गए। वे कलेक्टर सिंह से अफसरों की शिकायत करना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर भी ऑफिस में नहीं मिले। इस पर सभी गेट की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। एडीएम प्रकाश नायक ने वहां पहुंचकर अध्यक्ष और सदस्यों को समझाया। जिस पर वे माने और कलेक्टर के नाम अफसरों की शिकायत वाला आवेदन दिया।

मुख्यमंत्री-मंत्री से शिकायत करेंगे

अध्यक्ष राजपूत ने बताया- जनपद की बैठकों में संबंधित अधिकारी नहीं आते हैं और न ही मोबाइल कॉल रिसीव करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की क्या योजनाएं चल रही है? इस बारे में भी नहीं बताते हैं। इसलिए कलेक्टर के नाम शिकायती आवेदन दिया है। आगे से ऐसा होता है तो मंत्री और मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। इस दौरान जनपद सदस्य संतोष प्रजापति, लालचंद गुर्जर, रामदुलारी राकेश, हेमा नगीना, सरस्वती विश्वकर्मा, शशि पाल, अमर सिंह आदि मौजूद थे।

मप्र के 27 वकील बने सीनियर एडवोकेट

हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना, ओबीसी आरक्षण के पक्ष-विपक्ष वाले सीनियर अधिवक्ता भी सूची में

जबलपुर (नप्र)। मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करते हुए 27 एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट बनाया है। ओबीसी आरक्षण पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे जबलपुर के दो प्रमुख अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट बनाया गया है।

बता दे कि लंबे समय से मांग की जा रही थी कि सीनियर अधिवक्ताओं के नामों की अधिसूचना जारी की जाए, लिहाजा रजिस्ट्रार आफ जनरल ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की हैं।

ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के विपक्ष में खड़े अधिवक्ता आदित्य संघी को सीनियर एडवोकेट बनाया गया है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण के पक्ष में खड़े अधिवक्ता रामेश्वर सिंह को भी सीनियर एडवोकेट बनाया गया है। इनके अलावा अमित सेठ, अंजलि बनर्जी, अशोक लालवानी, एचएस रूपराह को भी सीनियर अधिवक्ता बनाया गया हैं।

भिंड में ट्रॉला-ऑटो की टक्कर, दंपत्ति और बच्चे की मौत

बेटे का इलाज करवाकर गांव लौटते समय हुआ हादसा

भिंड (नप्र)। भिंड में ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे-719 पर सोमवार-मंगलवार दरमियानी रात गिट्टी से भरे ट्रॉला ने एक ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दंपत्ति और दो साल के बेटे की मौत हो गई।

पावई क्षेत्र के दीखतन का पुरा में रहने वाले अनिल बघेल (31), पत्नी आरती बघेल (28) अपने दो साल के बेटे गणेश के साथ रात में अपने गांव दीखतन का पुरा लौट रहे थे। अनिल गुजरात में ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। कुछ दिन पहले वे गांव आए थे। बेटे की तबीयत खराब होने पर उसे ऑटो से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। रात करीब 11 बजे, वे ऑटो (जीजे 05 सीएक्स 4763) से गांव लौट रहे थे। दबोहा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रॉला (एचआर 38 एसी 0787) ने ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में तीनों को गंभीर चोटें आईं। आरती और बेटे गणेश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि अनिल को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उन्होंने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

एक ही चिता पर हुआ दंपत्ति का अंतिम संस्कार

देहात पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। मंगलवार सुबह तीनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। अनिल चार साल से सूरत में रहकर ऑटो चलाते थे और परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। 15 दिन पहले ही वे भिंड लौटे थे।

म.प्र.में बढ़ गए 35,186 बेरोजगार

सरकार ने 5 माह पहले 7.58 लाख बेरोजगार कम होना बताया था, अब प्रदेश में 26.17 लाख बेरोजगार

विधानसभा के शीत कालीन सत्र में बेरोजगारों की नई संख्या 26.17 लाख बताई

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में पांच माह में 35186 बेरोजगार बढ़ गए हैं। इसका खुलासा सरकार के जारी किए गए आंकड़ों में हुआ है। इसके पहले मई 2024 में सरकार ने विधानसभा में बेरोजगारों की संख्या 25 लाख 82 हजार 759 बताई थी। तब प्रदेश में 7.58 लाख बेरोजगार घटे थे।

अब विधानसभा के शीत कालीन सत्र में सोमवार को बेरोजगारों की नई संख्या 26.17 लाख बताई गई है। जिसमें 35186 बेरोजगार बढ़ गए हैं।

दरअसल, विधायक बाला बच्चन ने सवाल किया था कि 20 नवंबर 2024 की स्थिति में एमपी में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या और एक साल की अवधि में सरकारी और निजी क्षेत्र में चयन की जानकारी दी जाए।

इसकी कौशल विकास और रोजगार

राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने लिखित जानकारी में बताया है कि 20 नवंबर 2024 की स्थिति में बेरोजगार युवाओं के पंजीयन की संख्या 26 लाख 17 हजार 945 है। एक साल में 58351 युवाओं का चयन सरकारी और निजी क्षेत्र में हुआ है।

मैहर, पांढुर्णा, मऊगंज में भी बढ़े बेरोजगार

प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या को लेकर जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पांढुर्णा में सबसे कम 409 और भोपाल में सबसे अधिक 1 लाख 69 हजार 440 युवाओं के पंजीयन रोजगार के लिए हुए हैं। मऊगंज में 869, पांढुर्णा में 409 और मैहर में 841 युवाओं का पंजीयन बेरोजगार के रूप में है। इसके पहले वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में पांढुर्णा जिले में सबसे कम 9 बेरोजगार रजिस्टर्ड थे। साथ ही मैहर में 25 और मऊगंज में 144 युवा बेरोजगार रजिस्टर्ड रहे हैं।

जुलाई के बजट सत्र में 2023 के मुकाबले 7.58 लाख बेरोजगार घटना बताए थे

जुलाई में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कौशल विकास राज्यमंत्री गौतम टेटवाल ने सदन में जानकारी दी थी। उसमें 2023 के मुकाबले 7.58 लाख बेरोजगार कम होना बताए थे।

कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के जवाब में कौशल विकास और रोजगार विभाग से संबंधित जानकारी में सरकार ने कहा था कि 31 मई 2024 की स्थिति में रोजगार कार्यालय में दर्ज बेरोजगारों की संख्या 25 लाख 82 हजार 759 है। इसके पहले विधानसभा में 2023 में दी गई जानकारी में कहा था कि प्रदेश में पिछले साल 35 लाख 73 हजार बेरोजगार हैं।

सवा लाख इंजीनियर, 16 हजार एमबीए, 7 हजार डॉक्टर बेरोजगार

मध्यप्रदेश में करीब सवा लाख इंजीनियर और 16 हजार एमबीए क्वालिफाइड युवा बेरोजगार हैं। सात हजार डॉक्टरों के पास भी कमाई का जरिया नहीं है। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को जोड़ लें तो ये संख्या 11 लाख 70 हजार के पार पहुंच जाती है। बड़ी बात ये है कि ये आंकड़े सरकारी हैं। असल में बेरोजगारों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।

भोपाल में कमर्शियल टैक्स वसूली पर रोक

हाईकोर्ट पहुंचा था मामला, बीसीसीआई अध्यक्ष बोले- 6 जनवरी को होगी सुनवाई

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने भोपाल में नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे कमर्शियल टैक्स (वाणिज्यिक लाइसेंस शुल्क) पर फिलहाल रोक लगा दी है। टैक्स वसूली के विरोध में भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

(बीसीसीआई) हाईकोर्ट पहुंचा था। अध्यक्ष तेज कुलपाल सिंह पाली ने बताया कि अब 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। उन्होंने बताया, आज हुई सुनवाई में अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि संपत्ति का मालिक वाणिज्यिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा है, तो नगर निगम ऐसी फीस का भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। यह आदेश 6 जनवरी 2025 तक दिया गया है। इस दिन अंतिम सुनवाई होगी।

मंत्री, सांसद-मेयर के सामने उठा चुके मांग- बीसीसीआई ट्रेड (कमर्शियल) और प्रोफेशनल टैक्स को खत्म करने की मांग नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भोपाल सांसद आलोक शर्मा और महापौर मालती राय के सामने उठा चुका है। एक दिन पहले सोमवार को मंत्री विजयवर्गीय से मिले थे। इस दौरान अध्यक्ष पाली ने कहा था कि भोपाल को छोड़कर एमपी में यह टैक्स कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। इससे व्यापारियों पर बेवजह का दबाव पड़ रहा है। इस पर मंत्री ने चर्चा की और आश्वस्त किया था कि जब पूरे प्रदेश के किसी भी शहर में कमर्शियल लाइसेंस फीस लागू नहीं है, तो भोपाल एकमात्र ऐसा शहर क्यों है, जहां वाणिज्यिक लाइसेंस शुल्क लागू है। इस विषय पर विसंगतियों को हटाने का प्रयास करेंगे। चेंबर के अजय देवनानी ने बताया कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने टैक्स वसूली पर आगामी सुनवाई तक रोक लगाई है।

4 साल की बच्ची से बैड टच

चॉकलेट का लालच देकर ले जा रहा था युवक; रास्ते से गुजर रही महिला ने बचाया

भोपाल (नप्र)। भोपाल में चार साल की बच्ची से बैड टच का मामला सामने आया है। आरोपी लड़का बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने इंद्रपुरी स्थित जंगल के इलाके में ले गया। वहां से गुजर रही एक महिला ने बच्ची को रोते हुए देखा। खुद को फंसता देख आरोपी वहां से भाग निकला।

घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे की है। इंद्रपुरी में रहने वाली राखी मिश्रा अपने घर जा रहीं थी। इसी दौरान जंगल के पास एक युवक के साथ बच्ची रोती हुई नजर आई। राखी ने उन्हें रोककर बच्ची से पूछताछ की तो साथ वाला लड़का भागने लगा। उन्होंने दो ऑटो चालकों के साथ मिलकर उसका पीछा किया तो वह डिवाइडर से कूदकर फरार हो गया।

पिपलानी थाना प्रभारी अनुराग लाल ने बताया कि मामले में पूछताछ की जा रही है। अभी केस दर्ज नहीं किया गया है। बता दें कि, राखी मिश्रा गृहिणी हैं। वे एम्स से चेकअप करवाकर घर लौट रहीं थी।

सड़क पर रोती हुई मिली बच्ची- राखी मिश्रा ने बताया कि, मैं दोपहर करीब 3 बजे एम्स से चेकअप करवाकर लौट रही थी। इंद्रपुरी से एम्स आने वाली सड़क पर जहां खाली क्वॉर्टर्स बने हैं, उसकी सड़क पर बच्ची रोती हुई नजर आई।

वह एक युवक के साथ थी और बच्ची की अंडरवियर बच्ची के हाथ में थी। जब मैंने युवक से पूछा तो वह भाग गया। मैंने तुरंत बच्ची को अपनी कस्टडी में लिया।

दो ऑटो वाले वहां आए तो उन्होंने मेरे बताए अनुसार उस आदमी का पीछा भी किया, मगर वह वहां से भाग निकला। इसके बाद फिर वहां 3 अन्य महिलाएं भी आ गईं। इसके बाद हम लोग बच्ची को फौर पिपलानी थाना लेकर गए। जहां से हमने बच्ची के पेरेंट्स से संपर्क किया।

बच्ची का मेडिकल नहीं कराया- बच्ची के पेरेंट्स और उसे बचाने वाली राखी मिश्रा ने बच्ची को पूरी तरह से चेक किया, उन्हें बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, यह बिल्कुल भी नहीं लगा। मां ने कहा कि बच्ची ने पूछने पर बताया कि उस युवक ने पायजामा उतारकर बैड टच किया था। हालांकि बच्ची 1 घंटे में हमें मिल गई थी। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है।

चॉकलेट के बहाने ले गया आरोपी- मां ने बताया कि बच्ची पूरी तरह ठीक है। मैं बच्ची के साथ बाहर धूमने भी गई थी। वो सामने स्थित पार्क में झूला झूल रही थी, मेरा बेटा स्कूल से लौटा, तो मैं उसे अंदर छोड़ने गई। जब बाहर आकर देखा तो बच्ची झूले पर नहीं थी। जब थाने में मैंने बच्ची से पूछा तो उसने कहा कि उन अंकल ने कहा था कि वह चॉकलेट दिलाएंगे, इसलिए वह उनके साथ चली गई।

ग्वालियर में देवरानी-जेठानी से ठगे गहने, एफआईआर

सड़क पर झांसी जाने का पता पूछा; फिर नोटों की गड्डी दिखाकर उतरवा ले गए जेवरात

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में पता पूछकर ठगने करने वाली गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गई है। गैंग ने इस बार बाजार जा रही जेवरानी-जेठानी को टारगेट किया है। सड़क पर दो युवकों ने झांसी जाने का रास्ता पूछा फिर गहनों के बदले दो गुना नोटों की गड्डी दिखाकर महिलाओं को जाल में फंसाया। इसके बाद दोनों युवक महिलाओं से उनके गहने लेकर नोटों की गड्डी थमाकर चले गए।

युवकों के जाने के बाद जब महिलाओं ने नोटों की गड्डी देखी तो ऊपर

का एक नोट असली निकला, बाकी सारे नोट रद्दी निकले। घटना सोमवार शाम तानसेन मकबरा वाली गली ग्वालियर की है। घटना के बाद महिलाओं ने शोर भी मचाया, लेकिन जब तक कोई मदद के लिए आता, ठग वहां से भाग चुके थे। पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में जांच कर रही है।

ग्वालियर के चार शहर का नाका, इंद्रा नगर निवासी गुड़िया पत्नी सोनपाल तोमर गृहिणी है। दो दिन पहले वह अपनी देवरानी लक्ष्मी तोमर के साथ बाजार में खरीदारी के लिए जा रही थीं। अभी वह चार शहर का नाका इलाके में पहुंची ही थी कि तभी दो युवक उनके पास आए और झांसी जाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने रास्ता पता नहीं होने की बात कही। इसके बाद दोनों युवक उनके आगे-आगे चलने लगे। जैसे ही वह तानसेन मकबरा के पास पहुंची तो दोनों युवक फिर उनके पास आए और बताया कि उनके मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया है। वह भूखे हैं, इसके बाद वह बातों में उलझाकर दोनों महिलाओं को तानसेन मकबरा के पास वाली गली में ले गए।

नोटों की गड्डी दिखाकर ठगे गहने

दोनों महिलाएं जब युवकों से कुछ देर बात करती रहीं तो उनकी बातों में उलझ गईं। इसके बाद दोनों लड़कों ने बताया कि उनके पास नोटों की गड्डी है, जो वह अपने मकान मालिक की दुकान से उठा लाए थे। वह उनका गोल्ड दोगुना से ज्यादा कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके बाद पता नहीं युवकों ने क्या किया कि नोटों की गड्डी के बदले जेठानी (गुडिया) ने अपने मंगलसूत्र, ओम का पेंडल, कान के टॉप्स और उसकी देवरानी लक्ष्मी ने ओम का पेंडल, कान के टॉप्स उतारकर दे दिए। इसके बाद दोनों लड़के चले गए।

नोटों की गड्डी निकली रद्दी, शोर मचाया

दोनों लड़कों के जाने के बाद महिलाओं ने थैले में रखी नोटों की गड्डी खोलकर चेक किए तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि नोटों की गड्डी में ऊपर सिर्फ एक-एक पांच सौ रुपए का नोट लगा था और नीचे सिर्फ कागज लगे थे। इसके बाद उनको समझते देर नहीं लगी कि वह ठग चुकी हैं। मामले का पता चलते ही पीड़ित देवरानी और जेठानी ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। महिलाओं के साथ घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गुड़िया की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

ऐसा है ठगों का हुलिया

ठगी की शिकार महिलाओं ने बताया कि, एक बदमाश की उम्र करीब 35 साल थी और उसने चौखाने की शर्ट पहनी हुई थी और दूसरे की उम्र करीब 25 साल थी। उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी। दोनों हुलिया से शहर के ही लग रहे थे।

पहले भी घटी है घटना

यह ठगी का पहला मामला नहीं है। पिछले महीने ही कंपू, माधौगंज व कोतवाली इलाके में इस तरह की तीन वारदात हो चुकी हैं। उस समय वारदात करने के बाद ठग खामोश हो गए थे। पर एक बार फिर शहर में उन्होंने हलचल मचा दी है।

ग्वालियर थाना प्रभारी मिर्जा आसिफ वेग ने कहामहिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। ठगों का पता लगाने के लिए घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।

हमीदिया अस्पताल के वार्ड बॉय-टेक्नीशियन फिर हड़ताल पर

तीन महीने से सैलरी नहीं मिल रही; पिछली हड़ताल में दी गई डेडलाइन खत्म, मरीज परेशान

भोपाल (नप्र)। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर और हाउस कीपिंग स्टाफ मंगलवार सुबह से फिर हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल, हफ्ते भर पहले 10 दिसंबर को 500 से अधिक वार्ड बॉय और टेक्नीशियन हड़ताल पर थे। सुबह 7 बजे से सभी कर्मचारी अस्पताल के सामने धरने पर बैठे थे।

हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के परिजन खुद ही व्हील चेयर और स्ट्रेचर धकाते नजर आए। हड़ताल के चलते वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन और हाउस कीपिंग स्टाफ ने काम रोक दिया है।

हमीदिया अस्पताल के वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन और हाउस कीपिंग स्टाफ को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके चलते स्टाफ ने मंगलवार सुबह से फिर से हड़ताल कर दी है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। वह लगातार कंपनी और अस्पताल के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि हम लोगों को घर बार के खर्च चलाने में भारी परेशानी हो रही है। अगर हमें जल्द सैलरी नहीं दी गई तो हम यहां से कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाल कर प्रदर्शन करेंगे।मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिजन खुद स्ट्रेचर धकाते नजर आए।

इससे पहले बीते सोमवार को हड़ताल पर बैठे वार्ड बॉय ने बताया था कि हमने डीन मैडम से मुलाकात की है। उन्होंने शुक्रवार तक सैलरी और बोनस देने का आश्वासन दिया है। अगर शुक्रवार तक हमारी सैलरी नहीं आई तो हम लोग सोमवार को फिर से हड़ताल करेंगे। ऐसे में कर्मचारियों द्वारा पहली हड़ताल में दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है।

बता दें, हमीदिया अस्पताल में रोज 2500 से अधिक की ओपीडी रहती है। वहीं, 60 से अधिक ऑपरेशन होते हैं। हड़ताल के कारण इन सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

कर्मचारियों का कहा था कि दिवाली के समय तीन महीने की सैलरी बड़ी मुश्किल से दी गई थी। अब फिर से दो महीने का वेतन रोक दिया गया है। महंगाई के इस दौर में वैसे भी 8 हजार रुपए महीना मानदेय दिया जा रहा है। इसमें भुगतान में देरी हो रही है।

संपादकीय

एक साथ चुनाव : मंजिल अभी दूर

लगता है मोदी सरकार ने देश में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' व्यवस्था लागू करने की ठान ली है। इसी के तहत मंगलवार को केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इस संदर्भ में दो विधेयक लोकसभा में पेश किए। इनमें से पहला 129 वां संविधान संशोधन विधेयक है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश क़ानून (संशोधन) विधेयक है। सरकार ने ये विधेयक सदन में भले पेश कर दिया हो, लेकिन इसके पारित होने की राह में कई रोड़े हैं। चूंकि पहला और ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है, इसके लिए सरकार को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटाना होगा, जोकि बहुत आसान नहीं है। खासकर तब जबकि खुद भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। अलबत्ता दूसरा विधेयक सामान्य बहुमत से पारित हो सकता है। इसी के साथ विधेयक पर और विस्तृत एवं गंभीर चर्चा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने की भी तैयारी हो गई है। जेपीसी की सिफारिशों के बाद इसे सदन में पारित कराया जाएगा। गौरतलब है कि विगत 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। वन नेशन, वन इलेक्शन के पक्ष में सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही है कि इससे जहां चुनाव पर होने वाले भारी खर्च की बचत होगी, वहीं साल भर किसी न किसी न चुनाव में होने वाली ऊर्जा व धन की भी बचत होगी। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की संभावनाएं तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 191 दिनों की रिसर्च के बाद इस समिति ने 18 हजार 626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। सरकार ने इसे आजादी के 78 साल बाद होने वाला सबसे बड़ा चुनाव सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष के विरोध का मुख्य आधार सैद्धांतिक है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक संविधान में देश के संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। इस विरोध में छिपी यह आशंका भी है कि अगर लोकसभा व राज्यों के चुनाव एक साथ हुए तो सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को होगा। विपक्षी दलों को चुनाव आयोग की भूमिका और मंशा पर भी संदेह है। कोविंद समिति ने वन नेशन, वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने के लिए अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि यह योजना दो चरणों में लागू हो। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। जबकि दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर पंचायत और नगर पालिका जैसे स्थानीय चुनाव कराए जाएं। इन सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची का उपयोग हो। हालांकि देश में 1952 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। उसके बाद यह सिलसिला राज्यों में सरकारें तय अवधि के पहले गिर जाने के कारण टूट गया। नए चुनाव सुधार में असली पेच भी यही है। अगर सरकार बीच कार्यकाल में किसी कारण से गिर गई तो नया चुनाव न कराते हुए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि यदि सरकार बीच में गिर जाए तो जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी, वह संविधान सम्मत और जनभावना के अनुरूप होगी। इसका उद्देश्य सुशासन को जारी रखना और अगले चुनाव तक सरकार को ठीक से काम करते रहने का अधिकार देना है न कि कोई किसी राजनीतिक उठापटक को हवा देना है।

नजरिया

ललित गर्ग

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

यादगार हो सकता था संविधान पर चर्चा का सत्र

सर्वोच्च लोकतांत्रिक सदन लोकसभा संजीदा बहस की जगह हंगामे का केंद्र बनती जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण है। जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक बहस की जगह शोर शराबा, हंगामा और सदन का स्थगित होना ही आम होता जा रहा है। यही बात लोकसभा में संविधान को लेकर हुई दो दिनों की बहस की चर्चा के दौरान देखने को मिली। संविधान निर्माण के 75वें वर्ष पर हुई यह चर्चा भी छिछालेदार, आरोप-प्रत्यारोप एवं उच्छृंखलता का माध्यम बनी, जबकि संविधान पर इस चर्चा से जनता को एवं देश को सही दिशा मिलनी चाहिए थी, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दोहरायी जानी चाहिए थी। संविधान जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक बहस न होना लोकतंत्र को कमजोर करने एवं लोकतंत्र रूपी उजालों पर कालिख पोतना ही है। सत्तापक्ष और विपक्ष ने संविधान पर चर्चा के बहाने एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने का काम करके आकाश पर पैबंद लगाने एवं सछिद्र नाव पर सवार होकर संविधान रूपी सागर की यात्रा करने का ही संकेत देकर देश की जनता को निराश ही किया है।

भले ही अपने तर्कों एवं तथ्यों से पक्ष एवं विपक्ष ने अतीत के प्रसंगों और विषयों को अधिक रेखांकित किया गया हो। निश्चित ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग-अलग नजरियों को स्पष्ट करने वाली यह बहस न केवल समकालीन राजनीतिक मुद्दों पर बल्कि लोकतंत्र, समाज और इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने वाली रही, लेकिन इस बहस में आरक्षण, सावरकर, मनुस्मृति और अदाणी को शामिल करना विपक्ष की बुद्धि का दिवालियापन ही कहा जा सकता है। इनमें से अनेक प्रसंग और विषय ऐसे थे, जिन पर पहले भी किसी न किसी बहाने संसद के भीतर या बाहर चर्चा होती रही है। यह पहले से दिख रहा था कि विपक्ष संविधान पर चर्चा के बहाने यह बताने की कोशिश करेगा कि संविधान खतरे में है। लेकिन यह समझाने के लिए विपक्षी नेताओं के पास कोई मजबूत तर्क नहीं थे, वे यह स्पष्ट करने में विफल रहे कि आखिर संविधान को खतरा कैसे है? कांग्रेस संविधान पर चर्चा करते समय यह भी भूल गई कि वह यदि मोदी सरकार के एक दशक के कार्यकाल की गलतियां गिनायेगी तो उसे भी अपने चार दशकों के कार्यकाल की गलतियों हिसाब देना होगा। संविधान पर चर्चा के दौरान जैसे विपक्ष ने सत्तापक्ष पर आरोपों की झड़ी लगाई वैसे ही सत्तापक्ष ने भी विपक्ष पर आरोपों की बौछार की। लेकिन यह सब करते हुए पक्ष एवं विपक्ष ने संविधान की विशेषताओं को उजागर करने की सकारात्मकता की बजाय विध्वंसात्मक नीति का ही सहारा लिया।

जहां विपक्ष ने आरक्षण विरोधी आरोपों को दोहराते हुए कहा कि सत्ता पक्ष मूल रूप से आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है और जब-तब दबे-छुपे ढंग से उसकी यह अंदरूनी इच्छा संघ और पार्टी के छोटे-बड़े नेताओं के बयानों से जाहिर होती रहती है। जवाब में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की जो व्यवस्था

अभी लागू है, उनकी सरकार उस पर आंच नहीं आने देगी, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई भी कोशिश वह सफल नहीं होने देगी। जाहिर है, इसमें मतदाताओं को अपनी पाली में करने की दोनों पक्षों की कोशिश भी देखी और पहचानी जा सकती है। सत्तापक्ष और विपक्ष ने संविधान पर चर्चा के बहाने एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने का काम ईर्ष्या और मात्सर्य की भावना से किया, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास को ही बल दे रहा था। लगता है कि विपक्षी नेता यह समझने को तैयार नहीं कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने संविधान के खतरे में होने का जो हौवा खड़ा किया था, वह अब असरकारी नहीं रह गया है। विपक्ष के रवैये से यही लगा कि उसे यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल हो रही है कि जाति जनगणना कराने-न कराने से संविधान की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? कांग्रेस के लिये यदि जाति जनगणना इतनी ही आवश्यक है तो नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्यों नहीं कराई गई? अच्छा होता कि कांग्रेस नेता पहले इस प्रश्न का जवाब देते और फिर जाति जनगणना की आवश्यकता रेखांकित करते। लेकिन विपक्ष एवं विशेषकर कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद ही निरुत्तर होती रही है।

पूरी बहस में महापुरुषों को घसीटने का बिंदु ऐसा था जो न केवल बहस का जायका बिगाड़ने वाला कहा जा सकता है बल्कि यह निरुद्देश्यता एवं स्तरहीनता को ही दर्शाने वाला कहा जा सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह भी बताना चाहिए कि संविधान पर बहस करते समय सावरकर का नाम लेना और मनुस्मृति दिखाना क्यों आवश्यक हो गया था? कांग्रेस को यह समझ आ जाए तो बेहतर कि सावरकर, मनुस्मृति और अदाणी का उल्लेख करते रहने से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू-तू मैं-मैं चलती रहती है, लेकिन इसमें महापुरुषों को घसीटना अब बंद होना चाहिए। हमारे हर महापुरुष ने अपने समय, समाज और समझ की सीमाओं में रहते हुए कुछ ऐसा योगदान किया, जिसके लिए हम कृतज्ञ महसूस करते हैं। इसका मतलब उनके हर विचार से सहमति रखना या उनके हर कृत्य को समर्थन देना नहीं है। लेकिन उनके प्रति समाज की या उसके एक हिस्से की भी भावनाओं का सम्मान हमारी राजनीति का हिस्सा होना चाहिए।

सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी का पुराना आरोप भी उछला, लेकिन नई बात यह रही कि इस पर बचाव की मुद्रा अपनाने के बजाय कांग्रेस इस तर्क के साथ सामने आई है कि भाजपा को भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यहां इमरजेंसी जैसी कोई भाजपा की गलती बताने में कांग्रेस नाकाम ही रही। एक और बड़ी विडम्बना यह देखने को मिली कि संविधान निर्माण को किसी दल विशेष की देन कहा गया जबकि संविधान निर्माण में सभी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर विशेषतौर पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि पिछले कुछ वर्षों से देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है, जबकि वास्तविकता यह है कि संविधान के निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका रही है जिसे पूरी तरह से नकार दिया गया। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था, वह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि वह जनआकांक्षाओं का प्रतिबिंब था। उन्होंने कहा कि संविधान पार्टी विशेष नहीं बल्कि राष्ट्र का है, पार्टी विशेष ने संविधान निर्माण को हाईजैक कर लिया।

निश्चित ही संविधान देश का सुरक्षा कवच है। लोकसभा में संविधान पर बहस की मूल आवश्यकता उन कारणों पर बुनियादी चर्चा की थी जिनके चलते संविधान निर्माताओं के सपने अभी भी अधूरे हैं और नियम-कानूनों पर संविधान की मूल भावना के अनुरूप पालन नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, इसमें शक नहीं कि बहस का केंद्र यही सवाल रहा कि कौन संविधान और संवैधानिक मूल्यों को लेकर समर्पित है और कौन इस पर दोहरा खेल खेल रहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां सावरकर के सहारे भाजपा पर निशाना साधा वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की गलतियां गिनाईं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान के रूप में मिले सुरक्षा कवच को तोड़ा है। भारत का संविधान, संघ का विधान नहीं है। इसी बात को दोहराते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो देश एवं दुनिया भलीभांति देख रही है। मोदी के शासन में न केवल देश के भीतर शांति एवं अमनचैन बना है बल्कि सीमाओं पर भी सुरक्षा मजबूत हुई है। पडोसी देश भारत की ओर नजर करने का दुस्साहस नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अधिक सीमा की सुरक्षा एवं देश की सुरक्षा क्या हो सकती है? उचित होता संविधान पर चर्चा के दौरान बहस के स्तर को ऊंचा उठाते हुए आरोप-प्रत्यारोप से बचते हुए संविधान को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायक बनने वाले बिंदुओं पर सहमति कायम की जाती।

एक देश एक चुनाव

राजीव खंडेलवाल

लेखक कर सलाहकार और बैतूल सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष हैं।

संविधान संशोधन संघीय ढांचे पर अतिक्रमण कैसे?

संविधान लागू होने के 75वें वर्ष पर संसद में दो दिन पूर्व से हो रही संविधान पर चर्चा के दौरान पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक वर्ष पूर्व (सितम्बर 2023 में) गठित कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को रूबरू कैबिनेट ने स्वीकार कर 129 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया है, जिसे जेपीसी को भेजा जायेगा। यद्यपि इस संबंध में वर्ष 1983 से ही भिन्न-भिन्न समयों में चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग एवं संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस मूल आधार इस विधेयक का हैं। महत्वपूर्ण बात यह है की वर्ष 1952 से 67 तक हुए आम चुनावों में हुए एक साथ चुनाव की स्थिति वर्ष 67 के बाद से विभिन्न कारणों से व राजनीतिक परिस्थितियों के चलते अलग-अलग हो गई हैं। महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यहां यह है कि यह स्थिति कोई संविधान में संशोधन होने के कारण नहीं हुई है? परन्तु एक साथ चुनाव कराने में वापस आने के लिए जरूर प्रस्तावित संविधान संशोधन करना आवश्यक हो गया है। प्रश्न यह है की पूर्व स्थिति की पुर्नस्थापना के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित संविधान संशोधन से क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा ''केशवानंद भारती'' (वर्ष 1973) में प्रतिपादित सिद्धांत ''संविधान के मूलभूत (बुनियादी) ढांचा'' जिसे आगे भी कई अवसरों पर उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है, पर आंच आयेगी? क्या यह संघीय ढांचे पर अतिक्रमण है''?

संविधान निर्माताओं ने जब 5 साल के अंतराल में एक साथ लोकसभा व विधानसभा के चुनाव कराने की बात कही थी, तब उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि देश में दल बदल के कारण ''आयाराम-गयाराम'' की राजनीति के गिरते स्तर, लालच, धन, बल के चलते शैनः शैनः एक स्थिति ऐसी बन जायेगी, जब संवैधानिक प्रावधिक अवधि का पालन करने के कारण प्रायः अधिकतर राज्यों की विधानसभाओं व केंद्र के लोकसभा चुनाव अलग-अलग होने लगेगें। अतः वर्ष 1967 तक चुनाव एक साथ होते रहे हैं, जब वे संघीय ढ़ाचे पर अतिक्रमण नहीं थे, तब आज कैसे? जबकि किसी भी सरकार ने संविधान संशोधन द्वारा चुनावी अवधि की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया है। याद कीजिए! संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में ''एससी एसटी'' ''आरक्षण'' के लिए मात्र 10 वर्ष का प्रावधान किया था, और उक्त उद्देश्य की प्राप्ति न होने के कारण इसे हर आगे 10 साल के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया, जिसकी कल्पना तो उन्होंने कर ली थी। परन्तु यहां संविधान निर्माताओं ने शायद राजनेताओं के गिरते नैतिकता व गलत आचरण की कल्पना नहीं की थी, जो दुर्भाग्यवश आज व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है। इस कारण ही एक साथ चुनाव कराने का चक्र पांच साल की अवधि का क्रम टूटा है। तब फिर उसको सुधारने के लिए वही पुरानी चार चुनावों तक (52 से 67) चली व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए यदि आवश्यक संविधान संशोधन किया जाता है, तो वह संविधान की संघीय ढांचे के साथ छेड़-छाड़ या चोट कैसे! यह समझ से परे है।

15 विपक्षी पार्टियां का विरोध का आधार है, ''यह असंवैधानिक है''। ''संविधान की आत्मा पर चोट है''। यह संसदीय शासन प्रणाली में निहित विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाब देही के मूल सिद्धात को बिगाड़ देगा। साथ ही यह संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। ''विधानसभा की स्वायत्तता पर खतरा है''। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जायेगी। शासन विपक्ष युक्त देश चाहता है। आरएसएस का एजेड़ा लागू करने की कोशिश व ध्यान भटकाना, इन सबका सीधा जवाब है कि प्रारंभिक 20 वर्षों तक जब एक साथ चुनाव हो रहे थे, क्या देश में लोकतंत्र व संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा था? संघीय ढ़ाचा को चोट अनवरत बिना किसी विरोध के पहुंच रही थी? तब देश के किसी भी शख्स ने एक साथ हो रहे चुनाव के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।

एक बात और जो इस कदम के विरूद्ध में कही जा रही है, देश के एक साथ विधानसभा-लोकसभा को वोट देने पर देश में साक्षरता का स्तर कम होने के कारण लोग विवेक से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसका कुछ फायदा केन्द्र में बैठी सरकार की पार्टी को होता है। विशेषकर क्षेत्रीय दलों को नुकसान होता है। इस संबंध में अभी हाल के हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव का उल्लेख करने वाले ओडिशा के पिछले परिणाम को भूल जाते हैं। जब एक साथ चुनाव कराने में? उम्मीद के विपरीत परिणाम आये थे। अभी हाल में ही हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के साथ नादेड़ लोकसभा का उपचुनाव कराया था, जहां भी लोकसभा व विधानसभा में विपरीत परिणाम मिले थे। वस्तुतः यह जनता के विवेक पर ही प्रश्न-चिन्ह लगाने समान है?

यद्यपि आज की राजनीति में ''एक्शन की बजाय परसेप्शन'' का महत्व ज्यादा है, जिसे बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर है। उनके मुकाबले सिर्फ केजरीवाल ही ठहर पाते हैं। इसके लिए एक्शन करते हुए दिखना जरूर पड़ता है। परंतु इस मुद्दे को लेकर मोदी चूक गये लगते है। क्योंकि ''एक देश-एक चुनाव'' को लेकर प्रथम अवसर मिलने पर ही एक्सन कर परसेप्शन क्यों नहीं बनाया गया। पिछले एक साल की अवधि में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ही ले लीजिये! 7 फेसों में लोकसभा चुनाव की हुए चुनावी प्रक्रिया की अवधि कम की जा सकती थी। उड़ीसा विधानसभा के साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड व कुछ और राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ एक साथ कराया जा सकते थे, यदि चुनाव आयोग इनकी अवधि को 6 महीने आगे पीछे घटा-बढ़ा कर लेता, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। वर्ष 2022 में गुजरात के साथ हिमाचल के भी चुनाव कराये जा सकते थे, जो पहले होते थे। तब शायद जनता के मन यह परसेप्शन जरूर जाता कि सरकार वास्तव में इस विषय पर गंभीर है और वह बिना संवैधानिक संशोधन किये इस दिशा में जो कदम उठा सकती है, उठा रही है। एक तथ्य यह भी है कि इसके लिए दोनों सदनों में आवश्यक संख्या बल से एनडीए फिलहाल कोसों दूर है। पंचायती राज लागू होने के बावजूद पंचायतें, नगरपालिकाओं को इस संशोधन की परिधि में न लाकर इस मुद्दे की थोड़ी हवा जरूर निकाल दी है। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीच में विधानसभा भंग होने पर उसका चुनाव 5 साल के लिए न किये जाकर शेष अवधि के प्रावधान के लिए किया है। शायद यह प्रस्तावित संशोधन जरूर संविधान की मूल अवधारणा को (अवधि कम करने के कारण) चोट पहुंचा सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की राय भी ली जा सकती है।

वास्तव में यदि राजनीतिक दल व जनता यह चाहती है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ हो, और यह क्रम आगे भी निरंतर चलता रहे। तब फिर दल बदल को पूर्णतः प्रतिबंधित कर और बीच में सरकार किसी भी मुद्दे के गिरने पर शेष अवधि के लिए ''अल्पमत सरकार'' को कार्य करते हुये देना होगा। अथवा पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत द्वारा वर्ष 2015 में सरकार को एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव के संबंध में दिया गया यह सुझाव महत्वपूर्ण हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव की जगह ''रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव'' का प्रावधान करना होगा। वैसे यदि देश में पूर्ण रूप से न सही तो 90 प्रतिशत सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ एक साथ हो, तब भी वह देश की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक नेशन एक इलेक्शन ही कहलायेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक देश एक टैक्स की नीति के तहत जीएसटी वर्तमान में विभिन्न टैक्स दरों के साथ लागू है। एक साथ चुनाव कराने वाले के पक्षधर विश्व के कई देश अमेरिका, कनाडा, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड इत्यादि देश में एक साथ चुनाव कराये का उदाहरण दे रहे है तो फिर इन्हीं देशों का बैलेट पेपर से चुनाव कराये जाने को क्यों नहीं अनुसरण कर रहे है? इसका जवाब नहीं मिल पायेगा। सुविधा के अनुसार मुद्दों को चुनने की राजनीति प्रत्येक पक्ष करता है।

काश! हर शहर इंदौर सा खूबसूरत होता

विचार

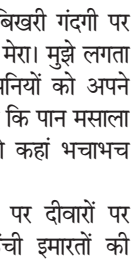

सुरेश सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

सुबह उठना है, सबसे पहले बल्टी उठाया दरवाजे के सामने पड़ी-बिखरी गंदगी पर पानी फेरा। रोज का यह काम है मेरा। मुझे लगता है पान मसाला बेचने वाली कंपनियों को अपने रैपरों पर यह जरुर लिखना चाहिए कि पान मसाला खाने वालों को उसकी पीक को कहां भचाभच थूकना है, कहां नहीं थूकना है।

पान मसाला खाकर सड़कों पर दीवारों पर थूकने वाले.. अस्पतालों व ऊंची इमारतों की

खिड़कियों से अपना मुंह लटका कर निकाल पान मसाले की पीक उगलने वाले, पिचकारी चलाने वाले यह दुर्लभ जीव स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं। गंदगी की रही सही कोर-कसर आवारा, जिसे लोग अब बेसहारा कहने लगे हैं वह जीव-जन्तु पूरी कर रहे हैं। आवारा जानवर गंदगी करते हुए महंगी टाइल व हौट मिक्स से बनी सड़कों को लाल-पीला-नीला करके मन में वितृष्णा पैदा करते हैं। पॉलिथीन पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह दुनिया भर में प्रचार हो रहा है, उस पर प्रतिबंध है, पर कहां है ईश्वर जाने? तमाम व्यवसायिक कंपनियों के, राजनीतिक पार्टियों के, अधिकारियों के सूचना वाले, शुभकामना संदेश वाले, प्लास्टिक के बैनरों-होर्डिंगों से ज्यादातर चौराहे, ऊंची दीवारें,ऊंची छतें अटी पड़ी हैं फिर पालीथीन पर पाबंदी लगाए तो लगाए कौन? मैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले खीरी के मुख्यालय लखीमपुर में रहता हूँ। यहाँ भी यही हाल है। यूँ तो नगर पालिका अध्यक्ष डॉ इरा श्रीवास्तव ने पर्यावरण संरक्षण पर काफी कार्य किया है, लोगों से साफ सफाई के लिये पालीथिन हटाने के लिये कहती भी रहतीं हैं, पर उनके विचारों पर न नगर वासी ध्यान देते हैं, न ही संजीदा लोग, उनके विचारों पर अमल करतें हैं।

मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था कि एक नगर पालिका अपने क्षेत्र में स्वच्छता पर करीब चालीस-पचास लाख प्रतिमाह अपने कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च करती है, पर उसके खर्च पर पलीता कौन लगाता है । जहां-तहां पान मसाला थूकने वाले, आवारा गोवंश, श्वान पालकर रास्ते में उन्हें फारिग कराने वाले, प्रयोग किये सेनेटरी पैड डाइपर जहाँ तहाँ फेंकने वाले.....यहां का कूड़ा वहां, वहां कूड़ा यहां, कूड़ा गाड़ियों की यह परिक्रमा, प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। उत्तर प्रदेश की अधिकतर नगर पालिकाओं, नगर निगमों के पास कूड़ा निस्तारण की उसे डंप करने की, रिसाइकिलिंग करने की कोई ठोस वैज्ञानिक तकनीक नहीं है, यह कब बन पायेगी ईश्वर ही जाने। स्वच्छता अभियान पर फोटोबाजी और दिखावा ज्यादा हो रहा है और जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण काम नहीं हो पा रहा है। जिससे लोग गंदगी से मुक्ति पा सके। बीमारियों से मुक्ति पा सके। हर शहर इंदौर जैसा खूबसूरत और स्वच्छ हो, यह जिम्मेदारी कार्यपालिका और आम लोगों की भी है?।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

लेखक व्यंग्यकार हैं।

राजनीतिक रोटी और समाजवादी मसाला

राजधानी के केंद्रीय कार्यालय में आज फिर से एक ऐतिहासिक घटना घटने जा रही थी। मुख्यमंत्री जी, जो पिछले कुछ दिनों से अपने कार्यों की 'सतत सफलता' का प्रचार करते नहीं थक रहे थे, आज पूरी तन्मयता से संगठन और प्रशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह संतुलन कुछ ऐसा था जैसे कोई संतुलन न हो, बस एक ऐतिहासिक त्रासदी हो।

मुख्यमंत्री साहब का पंच वाक्य था, 'हमने प्रशासन को चुस्त किया है, अब संगठन को गड्ढे में डालने का वक्त आ गया है।' सुनने वाले अफसरों को लगा, शायद वे कोई कुशल क्यूरेटर हैं, जो किताबों के बीच धूल झाड़ने के बजाय किसी विशाल जंग का आयोजन कर रहे हों। प्रशासन को चुस्त और सक्षम बनाने की उनकी भावना इतनी सशक्त थी कि वह खुद मानने लगे कि प्रशासन ही इस राज्य का एकमात्र सर्वेसर्वा है। बाकी सब तो पंक्तियाँ हैं, जो कभी भटक जाती हैं, कभी खुद रास्ते खोज लेती हैं।

संगठन वाले बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनका समय आ गया था। उन्होंने यह सोचकर समाजवाद के झंडे तान दिए थे कि जब तक समाजवाद की हवा बहती रहेगी, तब तक उनके स्वार्थ पर कोई आँच नहीं आएगी। समाजवाद तो जैसे 'कला' हो, जो कभी खत्म नहीं होती। नेता, कार्यकर्ता, अफसर-सभी एक-एक रंग के पंख लगाए हुए थे, ताकि उन्हें समाजवाद के मखमली आसमान में उड़ने का मौका मिल सके।

मुख्यमंत्री के कानों में बस एक ही मंत्र गूंजता था- 'संगठन सबसे ऊपर है, प्रशासन पीछे रखना है।' यह रणनीति शायद किसी पुराने राजा की युद्ध नीति से निकाली गई थी, लेकिन इस बार गुस्सा और सत्ता का घमंड कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। अफसरों को अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस हुई, जैसे वे उस सीट पर नहीं, बल्कि किसी ट्रक के पीछे बैठे हों। मुख्यमंत्री जी जो कहते, वे तुरंत सच्चाई बन जाते थे। 'कभी भी हम निर्णय ले सकते हैं,' मुख्यमंत्री की आवाज में वह रौब था जो खुद उनके प्रशासन के भीतर से ही निकलता था, और उसी का शिकार संगठन भी था।

अब प्रशासन के लोगों ने यह महसूस किया कि वे हमेशा प्रशासन के चुस्त होने का राग अलापने वाले थे, लेकिन खुद कभी चुस्त नहीं थे। चाय की चुस्की लेते हुए एक अफसर ने कहा, 'अब तो हम भी यही कहते हैं, 'काम करने का तरीका बदलो, लेकिन काम कभी खत्म मत होने दो।' फिर एक बड़े अफसर ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, 'लेकिन यहाँ कौन सी चाय मिल रही है? यह तो अफसरों की पसंद है कि वह शरबत पिएं या फिर सत्ता के मीठे पानी में डूब जाएं।'

लेकिन संगठन का खेल तो और भी दिलचस्प था। उनका नया नारा था, 'समाजवाद की बात करो, सरकार गिराओ।' उन्होंने नेता को एक-एक आशीर्वाद दिया, जैसे गड्ढे में गड़ी मटकी को हर रोज सींचा जाता है, ताकि उसकी जड़ें और गहरी हो जाएं। उनकी आवाज में छुपा हुआ मतलब यह था- 'हम समाजवादी हैं, पर केवल अपने लिए।' जब तक गड्ढे में पानी था, उनका तंत्र मजबूत था। जैसे ही पानी की धारा बहने लगी, उनका खुद का बड़बोलापन हवा में उड़ने लगा।

आखिरकार, जब कोई भी अफसर न तो प्रशासन की चुस्ती पर ध्यान दे रहा था, न ही संगठन की समाजवादी चालों पर, तो उन्होंने खुद से सवाल किया, 'क्या यह राजनीति है या फिर कोई कॉमेडी शो?'

मुख्यमंत्री, जिनकी यह सोच थी कि सब कुछ उनका है, चाय से लेकर संगठन तक, एक दिन अचानक बोले, 'समाजवाद क्या है? यह तो हमारे खेल का नाम है। हम इसे खुद बुलाते हैं, खुद सजा देते हैं और फिर खुद मस्ती से नाचते हैं।' उनका मतलब साफ था–'समाजवाद नहीं आएगा, हम उसे बुलाएँगे।'

संगठन ने फिर से अपना किला मजबूत किया। अब उनका संदेश था, 'जो हमारी राह पर नहीं, वो समाजवाद के बारे में क्या जानेंगे?' और फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो महाकाव्य-सा भाषण दिया, जिसमें समाजवाद की छोटी-छोटी पंक्तियाँ लगाईं–'संगठन का नाम बढ़ाओ, समाजवाद से खिलवाड़ करो।' इस खेल में कोई हारने वाला नहीं था, क्योंकि सबका ध्यान यही था कि समाजवाद का नाम बोले, और फिर हार-जीत पर कोई सवाल न करें।

आखिरकार मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि अब प्रशासन और संगठन दोनों को एक साथ लाकर उस खेल का हिस्सा बनाया जाएगा जिसे राजनीति के मंच पर 'समाजवाद का डांस' कहते हैं। सबके बीच समाजवाद का नाटक चलता रहेगा–कभी टकराने वाले, कभी साथ-साथ चलते हुए, और कभी एक-दूसरे के खिलाफ।

'सानंद न्यास' सम्मान

दिनेश पाठक

(वरिष्ठ पत्रकार और सांस्कृतिक समीक्षक)

संगठन, सहकार और समरसता का 'सानंद'

मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा संगीत, संस्कृति एवं कला के संरक्षण में कार्य करने वाली संस्था को सम्मानित करने के लिए 'राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान' की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई। सम्मानित संस्था को 5 लाख की आयकर मुक्त सम्मान राशि और सम्मान पट्टिका भेंट की जाती है। वर्ष 2024 के लिए यह सम्मान इंदौर की सांस्कृतिक संस्था 'सानंद न्यास' को आज (18 दिसंबर) को ग्वालियर में तानसेन समारोह के शताब्दी आयोजन में दिया जाएगा। इंदौर के लिए 'सानंद' ऐसा पवित्र संगम है जहां गंगा, जमुना और सरस्वती के समान, शास्त्रीय संगीत, नाट्य और संस्कारित उत्सव की त्रिवेणी गत 35 सालों से अविरत प्रवाहित हो रही है।

इंदौर के मराठी भाषियों के लिए 'सानंद' एक पवित्र गंगा-जमुना संगम है, जहाँ संगीत, नाटक और शास्त्रीय संगीत की अविरत अमृत धारा प्रवाहित होती है। रवींद्र नाट्य गृह में केवल निमंत्रितों के लिए होने वाले निश्चित कार्यक्रमों के अतिरिक्त 'सानंद' इंदौर के समस्त मराठी भाषियों के लिए और अन्य भाषा-भाषी रसिक जनों के लिए वर्ष भर में 3 या 4 खुले प्रांगण में सार्वजनिक निःशुल्क कार्यक्रम 'फुलोरा' उपक्रम के अंतर्गत आयोजित करता है। 'फुलोरा' का अर्थ है पुष्प गुच्छ। 'सानंद' न्यास का ही एक अंग. फुलोरा के कार्यक्रम निःशुल्क होने से आयोजन- प्रयोजन के समस्त व्यय की राशि उन सभी रसिक संगीत प्रेमियों से एकत्रित की जाती है। इन कार्यक्रमों में से एक हर साल शरद पूर्णिमा की रात, विशाल पैमाने पर सानंदोत्सव नाम से आयोजित होता है।

यह स्पष्ट है कि इंदौर में मराठी भाषियों ने अपनी साधना, तपस्या और प्रयत्नों से एक अलग पहचान बनाई है। ऐतिहासिक परंपरा तो है ही, पर वर्तमान आर्थिक बिखराव के इस युग में परस्पर स्नेह, एकता और संगठन-समरसता का 'सानंद' एक अप्रतिम और अनुपम उदाहरण है, जो समस्त भाषा-भाषियों के लिए अनुकरणीय कही जा सकती है। इस न्यास को स्थापित करने का विचार शहर के प्रसिद्ध इंजीनियर सुधाकर काले को था। उन्होंने अपने इन विचारों से अपने कुछ घनिष्ठ साथियों को अवगत कराया, जिससे एक वार्षिक निश्चित धनराशि के एवज में संस्था के सदस्यों के लिए मराठी नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाए। इसमें सदस्यों के लिए पूरे साल के लिए सीट आरक्षित रहेगी। इस प्रकार के व्यवस्थित आर्थिक नियोजन के साथ 'सानंद न्यास' को स्थापित किया गया। 1994 से सानंद द्वारा मराठी नाटक का सिलसिला लगातार बना हुआ है, जिसने शहर में एक नया दर्शक वर्ग भी तैयार किया और इंदौर को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित भी किया।

संस्था के सचिव जयंत भिसे बताते हैं कि चार हजार से अधिक सदस्यों के साथ इसे देश का सबसे बड़ा कलाप्रेमी समूह होने का गौरव मिला। जनवरी 1993 में न्यास की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि शहर के मराठी भाषियों को कला और संस्कृति से वही हो भाषा में रूबरू कराया जा सके। तब गाहे-बगाहे कार्यक्रम होते थे। ऐसे में करीब 400 सदस्यों को एक साथ जोड़कर मराठी दर्शक समूह तैयार किया गया। स्थापना के समय से न्यास ने दर्शकों के लिए स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। जब दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें अलग-अलग समूह में बांटा गया, ताकि कोई भी कार्यक्रम सभी दर्शकों को देखने- सुनने को मिले। अब इसके पांच दर्शक समूह हैं, जिनके हर कार्यक्रम अलग-अलग समय पर होता है। 11 पदाधिकारियों के अलावा 'सानंद मित्र' नाम से युवाओं को भी जोड़ा गया जो इसका फील्ड मैनेजमेंट देखते हैं। बड़े कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग सहयोग देते हैं, जो 25 हजार दर्शकों की व्यवस्था संभालते है।

मासिक नाट्य प्रस्तुति संस्था का सबसे प्रमुख आकर्षण होता है। इसमें मराठी के किसी प्रसिद्ध नाटक का महीने में एक बार मंचन कराया जाता है। इसके साथ ही सानंदोत्सव, गुड़ी पड़वा और दिवाली पर विशेष कार्यक्रम होते हैं। वहीं न्यास के अनु उपक्रम 'फुलोरा' के तहत बड़े कार्यक्रम सभी रसिकों के लिए किए जाते हैं। यही वजह है अभी चार हजार दर्शक न्यास से जुड़ने की प्रतीक्षा में हैं। सानंद ने देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इसी कारण मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा उनका प्रतिष्ठित राजा मानसिंह तोमर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। यह पुरस्कार प्राप्त करना सानंद की पिछले 35 वर्षों की सतत मेहनत साधना व परिश्रम का प्रतिफल है। आज इस संस्था के 4000 सदस्य हैं।

सदस्यों के लिए महीने में एक बार नाटक,फिल्म या संगीत का कार्यक्रम होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, उसका सही समय पर प्रारंभ होना। सभी का स्थान पूर्व निर्धारित होता है। आप किसी कारणवश देर से भी पहुंचे तो भी आपको आपका स्थान खाली मिलेगा। सानंद के कार्यक्रमों के लिए सभागार समय के साथ बदलते गए, पर आपको इन कार्यक्रमों में कभी भी किसी किस्म का शोर सुनाई नहीं दिया। यहां तक कि आपस में बात तक नहीं होती। हाथ हिलाकर मूक अभिवादन से ही भावनाएं व्यक्त होती हैं और सब कुछ स्वेच्छा स्व-अनुशासन और स्वविवेक से। नाटक का परदा उठता है हाल में अंधेरा और सन्नाटा और सभी डूब जाते हैं सानंद में आनंद उठाने के लिए। कभी नाटक पसंद न भी आए तो लोग इंटरवल का इंतजार करते हैं या जरूरी होने पर चुपचाप निकल जाते हैं। मध्यांतर का समय होता है परिचितों से मिलने का उनके हाल-चाल पूछने का। फिर लगभग सभी एक-दूसरे को जानते हैं नाटक के में डूबे लोग। नाटक के अलावा कोई चर्चा ही नहीं करते।

मध्यांतर की घंटी बजते ही सभी अपने-अपने स्थान पर लौट जाते हैं। न कोई शोर न कोई धक्का-मुक्की। नाटक खत्म होते ही कोई घर जाने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि वंदे मातरम का गान होता है। सारे दरवाजे खुले होने पर भी भारत माता की जय-जयकार करने का पावन अवसर कोई खोना नहीं चाहता। इतने व्यवस्थित व अनुशासित माहौल में यह न समझिए कि मनोरंजन नहीं होता। प्रत्येक कामेडी पर तालियों की गड़गड़ाहट और हंसी से हाल गूंज उठता है। जन समुदाय को एकता के सूत्र में पिरोने, समय-समय पर राष्ट्रीय त्योहारों को एक अप्रतिम अनोखा व अभूतपूर्व आयोजन बनाकर राष्ट्र प्रेम व राष्ट्र चेतना जगाने व सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने व हर कार्यक्रम को उत्कृष्ट तरीके से सफल व सहज बनाने में सानंद न्यास के हर कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है। सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने की होड़ में लगे सशक्त माध्यमों के बीच अपनी संस्कृति-सभ्यता को सहजता से संजोकर इससे नई पीढ़ी को अवगत कराने का जो दायित्व निस्वार्थ भाव से संस्था के अध्यक्ष श्रीनिवास कुटुंबले व सचिव जयंत भिसे वर्षों से निभा रहे हैं, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। आयोजन की सुखद अनुभूति

'सानंद' के एक सदस्य के अनुसार सचमुच उस समय एक बहुत सुखद अनुभूति होती है जब आप नाटक देखने के लिए नाट्यगृह में प्रवेश करते हैं। महिला दर्शकों को फूलों की वेणियां और पुरुषों को इत्रपान कराया जाता है और मकर संक्रांति को गुड़ तिल का वितरण भी। सब कुछ कितना सहज है और आत्मीय जैसे अपने ही परिवार के बहुत सारे लोग एक साथ किसी शुभ काम के लिए एक स्थान पर एकत्र हुए हों। ठीक सानंद बोध वाक्य की तरह 'मराठी असे आमुची मायवेतों, ग्या ही बढ़ाई सुकार्य विणे' अर्थात् मराठी हमारी मातृभाषा है मगर अच्छे कार्य किए बगैर इस बात की डींग हांकना बेकार है। इसी प्रेरणा वाक्य से प्रेरित इंदौर के मराठी भाषी समाज ने अपने कार्य के माध्यम से सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नई प्रेरणा एक नया उत्साह और एक नई रोशनी प्रस्फुटित की है।

सानंद के कभी न भूलने वाले आयोजन

'गोष्ट सांगा प्रतियोगिता' सफल व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों को गढ़ने में दादा-दादियों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता हैं। इसलिये दादा-दादियों के लिए गोष्ट सांगा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राहुल द्रविड अभिनंदन समारोह, पं. जसराज, भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी, पं. शंकर महादेवन, पं हरिहरन, उस्ताद जाकिर हुसैन का एकल तबला वादन, आशा भोसले, डॉ गुरूदेव शंकर अभ्यंकर की विविध विषयों पर व्याख्यानमालाएं, श्रीमंत बाबासाहेब पुरंदरे जो की व्याख्यानमाला, बाबा महाराज कीर्तन समारोह, सुरेश वाडकर, अशोक हाडे जी की अनेक कार्यक्रम, पं सुरेश तळवलकर ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से सानंद और इंदौर के रसिक श्रोताओं को अभिभूत किया है। 'सानंद' के नाटकों के माध्यम से विक्रम गोखले, सदाशिव अमरापुरकर, डॉ श्रीराम लागू, मोहन जोशी, रीमा लागू, भारती आचरेकर, वंदना गुप्ते, मृणाल कुलकर्णी, डॉ मोहन आगाशे, अतुल परचुरे, सुबोध भावे, सोनाली कुलकर्णी, प्रिया बापट, उमेश कामत, आनंद इंगळे, अदिती सारंगधर, प्रशांत दामले, वर्षा उसगांवकर, संजय नार्वेकर, महेश मांजरेकर, रोहिणी हट्टंगडी, डॉ गिरीश ओक, अशोक सराफ, सचिन खेडेकर, निवेदिता सराफ, शुभांगी गोखले, सुप्रिया पिलगांवकर, शैलेश दातार, राहुल सोलापुरकर, निखिल रत्नपारखी, डॉ अमोल कोल्हे, सिद्धार्थ जाधव, अमृता सुभाष अनेक दिग्गज कलाकारों ने अपनी अपनी कला प्रदर्शित करते हुए सैकड़ों संदेशप्रद नाटकों का मंचन किया। नाटकों के अलावा कई व्याख्यानमालाएं, सांगितक गोष्ठियां, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय कार्यक्रम,भी आयोजित किए जाते हैं।

चादणकी गांव

राजेन्द्र जोशी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

एक चूल्हा एक गांव, बुजुर्गों के अकेले रहने पर आया विचार

वर्तमान समय में आज देशभर में एक घर के अन्दर कई चूल्हे जलते हो,ऐसे में पूरे गांव के लिये एक चूल्हा जलना आपको विस्मित कर सकता है। लेकिन यह हकीकत है और कई सालो से यह चल रहा और एक चूल्हा जल रहा है। उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिला मुख्यालय से 41 किमी दूर स्थित चादणकी गांव में यह मिसाल देखी जा सकती है। एक चूल्हा एक गांव की बात जब हमने सुनी तो इच्छा हुई गांव को देखा जाये। जब दोपहर बाद गांव पंहुचे तो प्रवेशद्वार से पता लगा गांव खास होगा। आमतौर पर किसी गांव या नगर में प्रवेशद्वार नजर तो आते है,लेकिन दरवाजे वाला प्रवेश द्वार किसी गाँव मे पहली बार देखा। गांव में पंहुचते ही बाई और एक चोपाल नजर आई वहां की कुर्सियो पर कुछ लोग नजर आये जो गांव, समाज की कुरीतियों से सम्बन्धित चर्चा करते हुये मिले,सामान्य परिचय के बाद गांव के चतुर पटेल ने गांव के बारे में बताया कि गांव में अधिकांस बुजुर्ग और अधेड निवास करते है,बाद की पीढी उच्च अध्ययन,व्यवसाय और नौकरी के लिये अहमदाबाद,अमेरिका,आस्ट्रेलिया,कनाडा में है।

12 साल पहले एक चूल्हे का विचार आया

गांव के शान्तिलाल पटेल ने गांव में बुजुर्गो के अकेले रहने पर यह विचार किया कि सभी लोग बुजुर्ग है,ऐसे में खाना एक स्थान पर बनना चाहिये,सभी की सहमति के बाद गांव के 100 साल पुराने स्कूल भवन का संधारण कर सामूहिक किचन प्रारम्भ हुआ।

कैसे चलता है सामूहिक किचन

शान्तिलाल पटेल बताते है, प्रतिव्यक्ति 2500 रूपये का शुल्क भोजन के लिये रखा गया है,घर में मेहमान आने पर 50 रूपये प्रतिव्यक्ति शुल्क है। दीपावली और अन्य अवसरो पर भी सभी सामूहिक भोज करते है,इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है जो संचालन करती है,भोजनशाला वातानुकुलित है,उसी से लगा स्टोर रूम।

180 साल पहले गांव बसा था

गांव के 85 साल के रतिभाई पटेल बताते है,हमारे पूर्वजों ने 180 साल पहले देशरोज से आकर इस गांव को बसाया था,प्रारम्भ में गांव का नाम लक्ष्मीपुरा रखा गया था,लेकिन वह गांववालो को अच्छा नहीं लगा, उसके बाद गांव का नाम चांदणकी रखा गया।

गांव में कोई दुकान नहीं

इस गांव में स्थापना के बाद से किसी भी सामग्री की कोई दूकान नहीं है, नहीं गांव में कोई राज मिस्त्री,प्लम्बर,इलेक्टिशीयन,बढई,नाई,धोबी नहीं है,इन सभी कार्यो के लिये नजदीकी ग्राम बेचराजी जाना होता है। हमने पूछा ऐसा क्यो है,तो गांव के एक भाई ने जवाब दिया कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई,जरूरत पड़ने पर सामान ले आते है।

पुराने घरों के साथ आधुनिक घरों का निर्माण, खेती कोई नहीं करता

एक परकोटे के भीतर बसे इस गांव मे जहां पुराने समय के घर नजर आते है तो आधुनिक निर्माण भी जारी है। सम्पूर्ण गांव सम्पन्न किसानों का है, लेकिन नई पीढी के गांव में रहने के कारण बुजुर्ग खेती नहीं कर पाते है,इसलिये अधिकांश परिवार ने पास के किसानों को अपनी खेती बंटाव पर दे रखी है।

इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, कई पुरस्कार मिल चुके है। आजादी के बाद जब से ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रारम्भ हुये है,गांव में चुनाव नहीं हुये है,हर पांच साल में ग्रामवासी सर्व सम्मति से सभी को चुनते है। चादणकी ग्राम पंचायत को निर्मल व तीर्थ गांव के साथ सहकारी सोसायटी में जमा राशि के लिये पुरस्कार मिल चुके है।

परीक्षा परिणाम सौ प्रतिशत विद्यार्थी 5

गांव में प्राथमिक शाला है इसका परीक्षा परिणाम सौ प्रतिशत है,लेकिन विद्यार्थी मात्र 5 है। विद्यार्थियो की कम संख्या क्यो के सवाल पर प्रधान पाठक सदाजी भीकाजी ठाकोर बताते है,गांव के सम्पन्न लोगों के बच्चे शहरों और विदेशों में पढते है,यहां पढने वाले बच्चे तो मजदूरो के है।

600 से अधिक गांव वाले विदेशों में

गांव के अधिकांश परिवारो से नौकरी व्यवसाय और उच्च अध्ययन के लिये 600 से अधिक ग्रामवासी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा व अन्य देशो में रहते है,वही कई परिवार अहमदाबाद में रहते है।

स्मृति शेष

जयंत सिंह तोमर

लेखक स्वतंत्र अध्येता हैं।

गणेश परन के साथ तबले का पहला पाठ सीखा था उस्ताद ज़ाकिर हुसैन ने

गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लाँघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को सँभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था तारसप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर कभी-कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ़ सुनाई देती है यों अपने स्वर को ऊँचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए।

तबला के किंवदंती - व्यक्तित्व उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को तबले का पहला पाठ उनके पिता उस्ताद अल्लारखा ने गणेश - परन के साथ पढ़ाया था, जिसके बोल थे -

'गणानाम गणपति गणेश
लम्बोदर सोहे भुजा चार
इकदंत चंद्रमा ललाट राजै
ब्रह्मा विष्णु महेश ताल देत ध्रुपद गावैं
अति- विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावैं।।'

तबले का कोई मंदिर बने तो उसके चार प्रमुख स्तंभ होंगे पंडित किशन महाराज, उस्ताद अल्लारखा, पंडित कंठे महाराज, पंडित सामता प्रसाद (गुदई महाराज) और मंदिर के आमलक पर विराजमान चमकता कलश होंगे उस्ताद ज़ाकिर हुसैन।

उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के इस फ़ानी दुनिया से विदा लेने के बाद जैसे मंदिर का वह कलश ढह गया है। स्तम्भों पर रखा आमलक फिर किसी नवीन कलश की प्रतीक्षा में है।

उस्ताद ज़ाकिर हुसैन ने विनम्रता के साथ यह कहा भी था कि उनसे श्रेष्ठ तबला वादक मौजूद भी हैं और भविष्य में आयेंगे भी। लेकिन अभी तो उन जैसा सितारा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता जो तबले जैसे घनवाद्य को संगत की परिधि से उठाकर केन्द्र में ले आये। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के तबले के बोलों में ब्रह्मांड थिरकता था। कवि मंगलेश डबराल उनकी प्रस्तुति के बाद अगर 'संगतकार' कविता लिखते तो जरूर उसमें कुछ रद्दोबदल करते। वह कविता कुछ इस तरह है-

'मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूँज मिलाता आया है प्राचीन काल से।

गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लाँघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को सँभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था तारसप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर कभी-कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ़ सुनाई देती है यों अपने स्वर को ऊँचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए।'

आखरी चार पंक्तियों को फिर से पढ़ने का मन होता है तब उस्ताद ज़ाकिर हुसैन की याद आ ही जाती है -

'यों अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए।' संगत करते हुए उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के जीवन में जाने ऐसे कितने क्षण आये होंगे जब श्रोताओं ने परिधि पर बैठे कलाकार की पंचमुख से प्रशंसा की होगी, तालियां बजाई होंगी।

मुम्बई में सितारवादक पंडित रविशंकर के साथ संगत करते हुए एक बार ऐसा हुआ कि श्रोताओं द्वारा उस्ताद ज़ाकिर हुसैन की प्रशंसा से पंडितजी क्षुब्ध हो गये। पंडितजी चाहते थे कि सितार की तुलना में तबले पर लगे माइक की आवाज़ बीस फीसदी कम रहे।

उस्ताद ज़ाकिर हुसैन तबले के प्रमुख छह घरानों में से एक पंजाब घराने के प्रतिनिधि कलाकार की छवि से सन् 1973 के बाद निरंतर ऊपर उठते गये जब हिन्दुस्तानी, कर्नाटकी व पश्चिमी संगीत के फ्यूजन से एक के बाद एक बड़ी संगीत परियोजनाओं को सफल बनाया और ग्रैमी अवॉर्ड हासिल किए। गिटार - वादक जौन मैकलाफ्लिन, वायलिन वादक एल शंकर, आयरिश गायक मौरीसन, जियोवानी हिडाल्को, जेरी गार्सिया , संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, नीलाद्री कुमार से लेकर मिक्की हार्ट तक अनेक नाम शामिल हैं जिनके सहयोग से संगीत की ये वैश्विक परियोजनायें पूरी हो सकीं। भारत में उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को पद्मविभूषण, मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और संगीत नाटक अकादमी के रत्न सदस्य सम्मान से विभूषित किया गया। तमाम उपलब्धियों के बाद भी बनारस के कबीर चौरा की संगीत- गोष्ठियों और वहां के कलाकारों को वे बहुत आदर और आत्मीयता से याद करते रहे। उस्ताद अमीर खान और किशोरी अमोनकर को वे पिछली शताब्दी के महानतम संगीतज्ञों में मानते थे।

इन पंक्तियों के लेखक को उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के साथ एक फ्रेम में आने का अवसर भी मिला और नसरीन मुन्नी कबीर की उन पर लिखी किताब पर हस्ताक्षर लेने का भी। उस्ताद ज़ाकिर हुसेन के चित्र की पृष्ठभूमि में चित्रकार मनीष पुष्कले की कलाकृति है 'एक पत्थर की बावड़ी' जो ग्वालियर के आईटीएम विश्वविद्यालय के चांसलर रेजीडेन्स की बैठक की शोभा बढ़ा रही है। छायाचित्र खींचा था रुचि सिंह ने। एक छायाचित्र प्रसिद्ध शायर मदनमोहन मिश्र दानिश ने भी खींचा था।

उस्ताद ज़ाकिर हुसैन ने अंग्रेजी में लिखी अपनी जीवनी पर अंग्रेजी में और हिन्दी में अनूदित जीवनी पर हिन्दी में लिखा था। मुश्किल तब खड़ी हुई थी जब उस्ताद ज़ाकिर हुसेन के हाथों में दिया गया पेन ठीक से चल नहीं रहा था। तब मदनमोहन मिश्र दानिश जी से पेन लेना पड़ा।

खाद्य पदार्थ व विक्रय संस्थानों का निरीक्षण

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने जिले में कहीं भी दूषित खाघ पदार्थ का विक्रय ना हो पाए इसके लिए सतत निरीक्षण करने के निर्देश खाघ सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती एडलीन ई पन्ना ने बताया के प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय अमले द्वारा सघन जांच पड़ताल की जा रही है। पिछले तीन दिनों से औचक निरीक्षण की जानकारी देते हुए श्रीमती एडलीन ई पन्ना ने बताया कि बुधवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा शहर की दुकानें क्रमशः बाल विहार में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित इश्कृपा एजेन्सी से देशी घी, नमकीन, इडली मिक्स, खमंड मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स आदि के सैंपल तथा गुरुवार को श्री राम नगर स्थित धाकड़ ट्रेडिंग कंपनी (मसाला उद्योग) से लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर के सैंपल तथा रायपुर स्कूल के सामने स्थित अनमोल इंटरप्राइजेस से टारगेट ब्रांड गांठिया, टारगेट ब्रांड खट्टा मीठा, चना दाल नमकीन के सैंपल एकत्रित किए गए हैं। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं बिना खाद्य पंजीयन लाइसेंस के व्यापार ना करें। बिना खाद्य पंजीयन, लाइसेंस के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

तकनीकी प्रयोग एवं सायबर जागरूकता विषय पर वेबीनार

सीहोर (निप्र)। शाहगंज के शासकीय कॉलेज में तकनीकी प्रयोग एवं सायबर जागरूकता विषय पर राष्ट्रीय वेबीनार आयोजित किया गया। वेबीनार में विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी के महत्व एवं सायबर सुरक्षा पर अटैक के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही फिशिंग अटैक, द रेड फ्लैग, एसएमएस फिशिंग सोशल मीडिया फिशिंग क्लोन फिशिंग के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान विद्यार्थियों को बताया गया सायबर अपराध की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की जा सकती है।

डीएम इलेवन और सीईओ इलेवन के बीच खेला गया क्रिकेट मैच

सीहोर (निप्र)। सीहोर के बीएसआई ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में कलेक्टर इलेवन और सीईओ इलेवन क्रिकेट टीमों के बीच क्रिकेट मैच का मुकाबला खेला गया। कलेक्टर इलेवन की टीम की कप्तानी कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह और सीईओ इलेवन की टीम की कप्तानी प्रभारी जिला पंचायत सीईओ श्री नितिन टाले ने की। इसके साथ ही कलेक्टर इलेवन टीम ने इस क्रिकेट मैच में जीत हासिल की। इस 15 ओवर के मैच में कलेक्टर इलेवन की टीम ने 83 रन बनाकर 02 विकेट के साथ जीत हासिल की। इस मैच में सबसे अधिक 38 रन कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बनाए। इसके साथ ही सबसे अधिक 4 विकेट भी कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने लिए। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह मैन ऑफ द मैच रहे

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर क्रिकेट मैच संपन्न

हरदा (निप्र)। हरदा जिले में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया इनमें क्रिकेट मैच, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जांच शिविर, और प्रकृति परीक्षण जैसे कार्यक्रम शामिल थे। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आयुष विभाग के समन्वय से आयोजित किया गया। जिसमें जिला कलेक्टर श्री आदित्य सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव चौकसे डीएफओ, विभागीय अधिकारी एवं आईएमए के चिकित्सा अधिकारी तथा स्पंधन परियोजना जपाईगो से डॉ प्रतीक्षा पाल एवं उनकी टीम भी शामिल हुए। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं आईएमए के बीच क्रिकेट मेच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य एक साझा जिम्मेदारी है। इस प्रकार के आयोजन समुदाय को एकजुट करके फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश देते हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग द्वारा हेल्थ चेकप केम्प एवं प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।

सशक्त वाहिनी की छात्राओं के बीच खो-खो मैच

हरदा (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग के (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) अभियान के तहत संचालित सशक्त वाहिनी कक्षाओं में छात्राओं को पुलिस भर्ती एवं अन्य व्यवसाय में रोजगार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं खेल संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। सशक्त वाहिनी कक्षाओं की छात्राओं को जिले के अधिकारी भी समय समय पर मार्गदर्शन देने के लिए आते है। महिला सशक्त वाहिनी में पंजिकृत छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी एवं पुस्तकों की व्यवस्था भी की जाती है। रविवार को खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से नेहरू स्टेडियम हरदा में फिजिकल क्लास का आयोजन किया गया। उसके बाद सुकन्या टीम एवं लाड़ली टीम के बीच खो-खो मैच का आयोजन किया गया सुकन्या टीम ने निर्धारित समय 7 मिनट की पारी में लाडली टीम के 6 खिलाड़ी आउट किए , जबकि लाडली टीम ने सुकन्या टीम के 4 खिलाड़ी आउट किए, इस तरह मैच में सुकन्या टीम विजेता रही। सुकन्या टीम के सभी खिलाड़ियों को कलेक्टर श्री आदित्य सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव चौकसे ने गोल्डन मेडल प्रदान किए। इस अवसर पर विजेता टीम की कप्तान नंदनी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोनो छपे प्रथम ट्राफी प्रदान की गई।

विधायक राय एवं नपा अध्यक्ष राठौर ने सीसी रोड का किया भूमि पूजन

सीहोर (निप्र)। विधायक श्री सुदेश राय एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर ने सीहोर के वार्ड क्रमांक 9 में लगभग 12 लाख रूपये लागत के सीसी रोड़ के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक श्री सुदेश राय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में देश-प्रदेश के साथ ही जिले में भी निरंतर विकास के अनेकों कार्य हो रहे है। उन्होंने कहा कि इस सीसी रोड के निर्माण के बाद नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

धार नगर के नव निर्वाचित मंडल अध्यक्ष का भाजपा कार्यालय में स्वागत समारोह

नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष पार्टी की मजबूती के लिए करें कार्य : मनोज सोमानी

धार। भाजपा जिला कार्यालय में सोमवार को धार नगर के दोनों नव निर्वाचित भाजपा मंडल अध्यक्ष जयराज देवड़ा और विशाल निगम का भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया साथ ही जिले के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है।

नगर सेनापति मंडल और ठाकरे मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर अभिनंदन करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार के कार्यक्रमों को जनता जनार्दन तक पहुंचाएं। सत्ता के साथ मिलकर जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। इसके साथ ही पार्टी की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को अच्छे से लागू करें। रचनात्मक कार्यक्रम और सेवा भावना से जनता के दिल को जीते। नए मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति से नगर में पार्टी को और

मजबूती प्राप्त होगी और साथ ही कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा।

इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष विश्वास पांडे, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ,जिला कोषाध्यक्ष मनीष प्रधान, आईटी सेल जिला संयोजक दीपक शर्मा ,जिला सह मीडिया प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी, पूर्व पार्षद अनिल जैन बाबा, कालीचरण सोनवानिया हुकुम लश्करी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर और नितेश अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि शिव पटेल, मंडल महामंत्री राजेश डाबी, पुरुषोत्तम चौहान, सन्नी होड़ा , युवा मोर्चा जिला महामंत्री अंकित भावसार, देवेंद्र रावल, गौरव जाट, महेश तुलसीराम बोडाने, सोनिया राठौर, करण पटेल, बादल मालवीय, राजेंद्र राठौड़, हरीश आर्य, महेश कदम, प्रभात गुप्ता, चिराग रघुवंशी घनश्याम सोलंकी सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया।

मुख्यालय पर कोई किसी की सुनने मानने को तैयार नहीं ऐसा क्यों..?

नर्मदापुरम। मुख्यालय अब मुख्यालय नहीं रह गया, मुख्यालय को मज़ाक बनाया जा चुका यहां न तो कलेक्टर अपने दिए गए आदेश का महत्व जानते हैं ना उनके आदेश का क्रियान्वयन हो पाता यही स्थिति विधायक के लिखे पत्रों को लेकर देखा जाने लगा जिन पर अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे... हालिया सोनतलाई सहित बिछुआ सहकारी समितियों में आर्थिक अनियमितता का मामला प्रकाश में आया जिसमें फर्जी आरो और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दो करोड़ तैंतीस लाख की खाद प्राप्त कर वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच अनियमितता पाई गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष है ने महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक को त्रिस्तरीय जांच समिति गठित कर त्रिस्तरीय जांच समिति से जांच करने पर पाया गया कि समिति प्रबंधक राजीव दीवान सहित तत्कालीन प्रबंधक गौरीशंकर वर्मा, तत्कालिक लिपिक विश्वास शर्मा के द्वारा समिति सोनतलाई और बिछुआ में बिना सी.बी. एस. सिस्टम के गलत फर्जी एस.वाय.एस. नम्बर के 29 आरो/ डीडी विपणन संघ के पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तुत खाद प्राप्त किए जाने में गम्भीर आर्थिक अनियमितता की है। इतना ही नहीं संस्था सोनतलाई और बिछुआ के रासायनिक खाद कैश क्रेडिट लिमिट खातों से अन्य संस्थाओं सहित शाखा पुरानी इटारसी के अमानत दारों के खातों में कूट रचना कर संस्था/बैंक के साथ धोखा-धड़ी किये जाने के लिये ये तीनों प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गए.. जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक ने तत्काल प्रभाव से समिति प्रबंधक राजीव दीवान, शाखा प्रबंधक गौरीशंकर वर्मा और लिपिक विश्वास शर्मा को निलंबित कर दिया। साथ ही, संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश शाखा प्रबंधक, इटारसी को दिए हैं लेकिन ताज्जुब पन्द्रह दिन हो चुले पुलिस एफआईआर दर्ज करने को राजी नहीं न बैंक अध्यक्ष एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, पर ऐक्शन लेने को तैयार है। मामले में कलेक्टर के आदेश सर्वोपरि होने से पहली बार एक तो समय से जांच और उसकी रिपोर्ट सही आ पाई.. फिर पुलिस महाप्रबंधक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती..? सुनने में आ रहा है कि विधायक के करीबी होने का लाभ राजीव दीवान को मिल रहा वो बैंक मैनेजर के साथ इटारसी में गलबहियां डाल धूम रहे हैं। दूसरा मामले में रेडक्रास सोसायटी की दूकान नं 4 दुकान आबंटन अनुबंध दो व्यक्ति ओमप्रकाश बरखने और गौरीशंकर बरखने के नाम के नाम पर हुआ था तो उस दुकान पर अकेले ओमप्रकाश बरखने का आधिपत्य कैसे हो गया..? गौरीशंकर इस मामले को लेकर सड़क पर घूम रहे उसे रेडक्रास सोसायटी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दे रही, सजग विधायक डॉ सीतासरन शर्मा इसे लेकर सीएमएचओ नो बार पत्र लिख चुके पर सीएमएचओ उनके पत्र को अहमियत नहीं दे रहे क्यों..? फिर अकेले यह दो मामले ही मुख्यालय का इतिहास नहीं। नगरपालिका नजूल रास्ते को बेंच रही प्रशासन और जनप्रतिनिधी खामोश है। नगरपालिका की जमीन पर निजी विद्यालय चलाया जा रहा, शिक्षा विभाग और प्रशासन खामोश है, सरकारी खेल मैदान पर खेल और युवा कल्याण विभाग अपना अधिकार नहीं दिखा पा रहा। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश जमीन के नामांतरण बंटवारे सरकारी रिकॉर्ड प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किए जाए प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। 1972 में सरकारी हो चुके एस एन जी स्कूल, नर्मदा महाविद्यालय, गर्ल्स कालेज आज भी सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम नहीं.. मुख्यालय पर आखिर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सांठ-गांठ में हो क्या रहा आम आदमी तो पूछ रहा..?

आईआरसीटीसी करवाएगा महाकुंभ पुण्य यात्रा, चलेगी स्पेशल ट्रेन

देवास/मोहन वर्मा। रेल्वे के आईआरसीटीसी द्वारा आगामी 21जनवरी से प्रयाग महाकुम्भ के लिए 05 रातों और छह दिन की 'पुण्ययात्रा' करवाई जा रही है। इंदौर से शुरू यह यात्रा ट्रेन देवास से होकर गुजरेगी पश्चिम रेल्वे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने आज एक जानकारी में बताया कि महाकुंभ के अवसर पर आईआरसीटीसी विशेष ट्रेन से यात्रियों को प्रयागराज,वाराणसी और अयोध्या की यात्रा करवाने जा रहा है। इंदौर,देवास,भोपाल होकर ये ट्रेन गंतव्य तक पहुँचेगी। पांच रातों और छह दिन की इस पुण्य यात्रा की इस विशेष ट्रेन मे स्लीपर का किराया 19950/- तथा 3ह्स्र एसी का किराया 27700/- प्रति व्यक्ति होगा जिसमें भोजन,आवास, सड़क परिवहन और दर्शनों की सुविधा होगी। इस भारत गौरव ट्रेन की बुकिंग ऑनलाइन तथा बड़े स्टेशन की खिड़की से भी की जा सकती है। इस ट्रेन में सामान्य के छह तथा एसी का एक कोच होगा। महाकुम्भ के लिए खास चलाई जा रही इस भारत गौरव ट्रेन मे सुविधाजनक रूप से यात्रा कर महाकुंभ का आनंद लिया जा सकता है। इस सम्बंध में रतलाम जनसंपर्क के मुकेश पांडे, आईआरसीटीसी के सुशील पाटिल तथा देवास रेल्वे प्रबंधक राम सागर यादव ने भी जानकारी साझा की।

कार्यपालक निदेशक ने मोगरा फूल ग्राम पंचायत परिसर का किया निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ धीरेंद्र कुमार पांडे सीहोर विकासखंड के अंतर्गत मोगरा फूल ग्राम पंचायत परिसर में वाटिका का निरीक्षण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्राथमिकता देन के साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबन के लिए प्राकृतिक एवं सौर ऊर्जा को अपनाना आवश्यक है। इसके लिए हमें समाज के साथ मिलकर काम करना चाहिए तथा समाज को शिक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा की प्रत्येक नवांकुर संस्था अपने सेक्टर में आदर्श ग्राम बनाने के लिए नर्सरी निर्माण, वाचनालय एवं जन सूचना केंद्र का प्रसार करना चाहिए । इसके साथ ही अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने आदर्श ग्राम मोगरा फूल में वाचनालय एवं जनसूचना केंद्र का शुभारंभ किया एवं वाटिका का अवलोकन किया तथा पौधारोपण किया। इस दौरान श्री वरुण आचार्य, श्रीमती पारुल उपाध्याय, श्री प्रदीप सिंह सेंगर सहित नवांकुर संस्था प्रतिनिधि, मेंटर्स, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सदस्य, छात्र एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे।

नकली नोटों पर छपा राष्ट्रपिता का फोटो, सड़कों पर पड़े मिल रहे, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा

देवास। व्यापार करके कमाना कोई बुराई की बात नहीं है लेकिन व्यापार के साथ पैसे कमाने की भूख इतनी ज्यादा हो जाना की मान अपमान सब भूल जाया जाए आजकल शहर की अनेक दुकानों पर बच्चों के खेलने के लिए भारतीय मनोरंजन बैंक के नाम से 500, 200 , 100, 50 ,20 रुपए के नकली नोट बच्चे खरीद रहे हैं और उनसे खेल रहे हैं और उन्हें सड़कों पर भी फेंक रहे हैं । कई लोग असली नोट समझकर उसे उठाते हैं लेकिन देखने के बाद फिर से फेंक देते हैं लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उस नकली नोट पर देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो छपा हुआ है जो सड़कों पर पैरों में आ रहा है।

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व कार्यकारी अध्यक्ष

प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि इन नकली नोटों को छापने के दौरान यह तो ध्यान रखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जगह भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा गया है वही एक छोटा सा मोनो कॉर्नर पर बनाया गया है वही लिखा गया है, मैं हूं करोड़पति बाकी नोट को हु बहू बनाया गया है। नकली नोट छापने वाली फॉर्म ने यह नहीं समझा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो की जगह कोई अन्य मनो बना दिया जाता इसी के साथ 500 के नोट के पीछे लाल किले की आकृति छापी गई है साथ ही वहीं अन्य नोटों पर जो आकृति अंकित की गई है उन्हें भी हूं बहू बनाया गया है। इन नोटों को छापने के दौरान यह बाजार में चलाने के दौरान किसी भी राष्ट्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ने आपत्ति नहीं ली इस कारण नोट छापने वाली फॉर्म को और बढ़ावा मिला वहीं नकली नोट छाप कर बाजार में बच्चों के लिए बेचने के दौरान बड़ा मुनाफा भी सामने आया है। कांग्रेस की मांग है की रिजर्व बैंक, भारत सरकार इस संदर्भ में शीघ्र संज्ञान ले एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र को नकली नोट पर से हटवाए साथ ही नोट के पीछे छापी राष्ट्रीय धरोहरों की फोटो भी हटाई जाए।

शहर कांग्रेस द्वारा इस संदर्भ में रिजर्व बैंक को एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। जिसमें मांग की गई है कि इन नकली नोटों पर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र एवं राष्ट्रीय धरोहरों के फोटो तत्काल हटाये जाए

शीतलहर का प्रकोप ठंड से बचने अलर्ट जारी मंदिरों में भगवान को ओढ़ाए गरम वस्त्र

मंडीदीप, निप्र। प्रदेश सहित जिले के औद्योगिक नगर में भी शीतलहर का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह जहां सूर्य की किरणें कोहरे से ढकी होती है वहीं शाम को 4 बजे से ही दिन ढलता नजर आता है।

शीतलहर और ठंड से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाईजरी जारी कर दी है। नगर में श्रीराम मंदिर,खेड़ापति मंदिर, श्रीराधाकृष्ण मंदिर,हनुमान कुटी सहित विभिन्न मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने गरम कपड़े उड़ाए जा रहे हैं। नपा ने भी नगर के प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाना शुर कर दिया है। जिससे नागरिकों को राहत है।

आठ स्थानों पर जलाए अलाव

नगर पालिका द्वारा भी ठंड से बचाव के लिए जगह-जगह अलाव जलवे जा रहे हैं। वहीं नागरिकों और व्यापरियों ने भी ठंड से बचाव के खुद ही प्रयास किये। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन सहित बाजार मैं दुकानों के सामने व्यापारी और आमजन अलाव में आग सेंकते नजर आए। वे गत्ते, कूड़ा और जलने लायक कबाड़ से अलाव जलाकर ठंड से बचने के प्रयास करते नजर आए।

मंदिरों में लगाये हीटर, ओढ़ाए गरम कपड़े

नगर के विभिन्न मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। पंडित गौरव शर्मा ने बताया कि सभी मंदिरों में भगवान को शॉल ओढ़ाए गयी है। ठंड के करण कुछ मंदिरों में सुबह और शाम की आरती का समय भी बदला गया है।आरती के समय आरती उद्यान स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में भगवान श्रीराधाकृष्ण को गर्म कपड़े ओढ़ाए गए। श्री राम मंदिर में श्रीराम जानकी और लक्ष्मण को गर्म कपड़ों के साथ मंदिर परिसर हीटर भी लगाया गया है। ऐसे ही नगर के अन्य मंदिरों में भी भगवान को ठंड से बचाने के उपाय किये जा रहे हैं।

गौशाला के संवर्धन प्रबंधों में हो रही बढ़ोतरी

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले की गौशालाएं अब नये स्वरूप में दिखने लगी हैं। यह सब कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह की नवाचार पहल से संभव हो रहा है। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने विदिशा जिले में चरनोई भूमि को अतिक्रमण से विमुक्त करने की कार्यवाही को अंजाम देकर गौशाला से मुक्त कराई गई भूमि को संबद्ध कर नए सूत्रपात से जन भागीदारी की पहल को बढ़ावा मिल रहा है। विदिशा जिले की शासकीय गौशालाएं अब आत्मनिर्भरता की ओर शनै शनै अग्रसर हो रही हैं। जिले में चरनोई भूमि से सबसे पहले अतिक्रमण हटाने की सख्त कार्रवाई बिना किसी भेदभाव से एक सुत्रीय मुहिम के रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं। अतिक्रमण हटाने के बाद मुक्त कराई गई भूमि पर पुनः और कोई कब्जा ना कर ले इसके लिए इस भूमि को क्षेत्र की गौशाला से सीधे टाइअप करने के कार्यों के साथ-साथ सुरक्षा के दृष्टि कोण से अतिक्रमण विमुक्त भूमि सहजता से जन सामान्य जान सकें इसके लिए चौतरफा तार फैंसिंग के कार्यो को मुर्तरूप दिया गया है। ग्यारसपुर तहसील के ग्राम कंजेला में बालाजी गौ संरक्षण संस्थान द्वारा भी इस प्रकार के नवाचारों की ओर अनायास सभी का ध्यानाकर्षण हो रहा है। हो भी क्यों ना यहां गौशाला के संवर्धन संबंधी पैरामीटरों को बेहतर ढ़ंग से पूरा कराया जा रहा है। पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति के लिए अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर घास उत्पादन लेना शुरू हो गया है यहा 7 बीघा में बर्शीम घास लगाई गई है। उगने वाली घास चारे के रूप में उपयोग की जा सकेगी। इसके अलावा गौशाला में घायल पशुओं के उपचार पशु-चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है। जबकि मृत पशुओं के लिए पृथक से संस्कार स्थान सुव्यवस्थित रूप से बनाया गया है जो संभवतः अन्य गौशालाओं में देखने को नहीं मिलता है। गौशाला में उत्सर्जित प्रदार्थो के लिए भी आवश्यक प्रबंधों को सुनिश्चित किया जा रहा है।

संसदीय परंपराओं के निर्वहन में मध्यप्रदेश विधानसभा का गौरवशाली इतिहास: श्री तोमर

मध्यप्रदेश विधानसभा की गौरवपूर्ण यात्रा के 68 वर्ष पर एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की गौरवपूर्ण यात्रा के 68 वर्ष पूर्ण होने पर एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया। सदन को संबोधित करते माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में राज्यों के विधानमंडलों की महती भूमिका रही है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपनी स्थापना के 68 वर्ष पूर्ण कर रही मध्यप्रदेश विधान सभा का संसदीय परंपराओं के निर्वहन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है।

श्री तोमर ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो मध्यप्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। पुनर्गठन के पश्चात् अस्तित्व में आई नई विधान सभा का पहला अधिवेशन 17 दिसम्बर 1956 को प्रारंभ हुआ था। उन्होंने कहा कि सात दशक के इस कालखण्ड में विधानसभा ने प्रदेश के विकास और यहां के नागरिकों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, वे सरकारों के माध्यम से धरातल पर उतरे और आज जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में 'विकसित भारत' के संकल्प की सिद्धी में द्रुतगति से जुटे हुए हैं, स्व. कुंजीलाल दुबे जी के शब्दों में मध्यप्रदेश, देश का गौरव बन रहा है।

श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश में विधानसभा ने संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों, परंपराओं एवं सदन संचालन के माध्यम से प्रदेश को एक सुशासित, जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी राज्य बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। इस कालखण्ड में मध्यप्रदेश विधानसभा अपने यशस्वी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों, प्रतिपक्ष के नेताओं, मंत्रियों, समिति सभापतियों, सम्माननीय सदस्यों एवं विधानसभा सचिवालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों के अतुलनीय योगदान एवं असाधारण सहयोग के बल पर सदैव जनकल्याण एवं प्रदेश के विकास को समर्पित रही है।

श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश विधान सभा ने सदैव महिला नेतृत्व को उभारने एवं उसके सशक्तिकरण की दिशा में भी कार्य किया है। मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रत्येक सत्र में प्रति मंगलवार को प्रश्नकाल में महिलाओं एवं प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों का प्रश्न लिये जाने का निर्णय लिया गया है। आज के दिन मंगलवार को भी प्रश्नकाल में हमारी 7 माननीया सदस्यों के प्रश्न तारांकित प्रश्नों में लिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा जन-सरोकारों से भी जुड़ी रही है। यहां आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का उल्लेख करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश का कोई भी नागरिक जिसका शासन स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ हो और उसके द्वारा शासन एवं अधिकारियों के समक्ष आवेदन देने के पश्चात भी कार्य का निराकरण नहीं हुआ हो तो वह आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति के समक्ष प्रमाण के साथ आवेदन कर सकता है। इस आवेदन पर समिति संज्ञान ले सकती है।

श्री तोमर ने कहा कि माननीय सदस्य जनता की आवाज होते हैं इसलिए विधान सभा अध्यक्ष के नाते मैंने पहल की है कि सदन में पहली बार चुनकर आए विधायकों को प्रोत्साहित किया जाए, उनकी आवाज अनुभव के आगे अनसुनी न रह जाए। सदन की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखते हुए यह व्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया है कि शून्यकाल की सूचनाओं में पहली बार चुनकर आये विधायकों की सूचनाओं को प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाय। पहली बार निर्वाचित तीन सदस्यों की सूचनाओं को उसी दिन स्वीकार किये जाने की व्यवस्था भी दी गई जिस दिन वे प्राप्त हुई थी। इस कदम को 16वीं विधान सभा में एक नई परिपाटी निरूपित किया गया। नवाचार को आगे बढ़ाते हुए एक और व्यवस्था दी गई कि प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। व्यवस्था के अनुसार 'अब विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे। इसके संबंध में परीक्षण कर प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा समिति द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।'

श्री तोमर ने इस बात पर बल दिया कि समन्वय, प्रशिक्षण और नवाचार की त्रिवेणी के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया है कि विधानसभा की कार्यवाहियां राजनीतिक विचार से ऊपर उठ कर जन सरोकारों का मंच बन सकें। प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से विधान सभा के कार्य को प्रभावी, पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह बनाने की दिशा में ई-विधान पोर्टल और मोबाइल एप एक उल्लेखनीय पहल है।

तोमर ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार

मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जयपुर में पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक पिरयोजना के त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित होने पर प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

श्री तोमर ने सदन में अपने उद्बोधन में कहा कि आज का दिन मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के भविष्य के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आज मध्यप्रदेश विधानसभा के 68 वर्ष पूर्ण होने का अवसर है और आज ही यह शुभ प्रसंग आया है यह भी संयोग है।

श्री तोमर ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने संदेश में कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक पिरयोजना दोनों राज्यों को ' सुजलाम्-सुफलाम्' बनाएगी। इससे मध्यप्रदेश के मालवा एवं चंबल के 11 जिलों में सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व संवर्धन होगा और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से यह परियोजना 20 वर्षों के लम्बे इतंजार के बाद मूर्त रूप ले रहीं है। परियोजना से श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर सहित आगर, इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर इत्यादि संपूर्ण पश्चिमी मध्यप्रदेश में पीने के पानी और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। परियोजना से प्रदेश के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा। मालवा और चंबल क्षेत्र में 6 लाख 13 हजार 520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा।

विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ का वार्षिक सम्मेलन संपन्न

उप मुख्यमंत्री शुक्ल हुए शामिल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि पेंशनर्स हमारे समाज की धरोहर हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सिंधु भवन भोपाल में विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के प्रादेशिक वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संघ की स्मारिका का विमोचन किया। संगठन प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री को पेंशनर्स की तीन प्रमुख मांगों - पेंशन की शासकीय गारंटी, महंगाई राहत का समय पर भुगतान और कैशलैस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने उपस्थित पेंशनर्स से आत्मीय संवाद किया।प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री आर.डी. मिश्रा, संरक्षक डॉ. शैलेन्द्र व्यास, और भोपाल शाखा अध्यक्ष बी.आर. मानकर सहित अन्य पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ग्वालियर अभ्युदय संगठन की कार्यकारिणी की बैठक

ग्वालियर। ग्वालियर अभ्युदय संगठन की कार्यकारिणी बैठक ग्वालियर में आयोजित हुई। दीप प्रज्वलन कर गणेशजी का आह्वान रीता जयसवाल ने किया। संगठन की कोषाध्यक्ष डॉ. मंजुला सिंघल ने गणपति जी की आरती गाई।, इस संगठन का ध्येय गीत जागो मातृशक्ति तुम जागो, जागो माता जागो , जागो बेटी जागो, जागो बहना जागो की रचना वीरवाला वर्मा ने की। ग्वालियर चैप्टर की तरफ से संगठन संरक्षिका आशा माथुर ने विश्व नारी संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष वाराणसी रीता जयसवाल का मोमेंटो,साल और मोतियो की माला से सम्मानित किया। डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.ओ. उपाध्यक्ष नगर हाफिजा मुजफ्फर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में औरतो की स्थिति पर ग्रास रूट पर चर्चा हो यह निराशा का विषय बना हुआ है । आज और कल,एडवोकेट अर्चना ने संगठन में जुड़ने से अपना अश्रुपूर्ण अनुभव इस संगठन को जाता है मुझमें परिवर्तन करने का।, मेजर डॉ. आशा माथुर राष्ट्रीय संरक्षिका ग्वालियर ने कहा कोविड मे शिथिलता आई थी इस संगठन से पर मेरा संवाद वाटसएप्प ऑनलाइन प्रोग्राम पर होता रहता था । मेरे लिए यही स्नेह प्रेम रूह नुमा है । आप भी आगे बढ़े मै भी चलूंगी। उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर बीना ने बताया अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.ओ. राष्ट्रीय सदस्य डॉ. अरुणा गंगाजली ने बताया महिलाओं के सम्मान में देश दुनिया कि महिला आज लड़ रहीं है स्त्री सम्मान की लड़ाई हम सबको लड़नी है। विश्व में कानूनी, स्वास्थ्य पर सामाजिक काम होना बहुत बाकी है। विश्व नारी संगठन के ग्वालियर चैप्टर की सचिव मीना शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

अंबेडकर पार्क में मनाया पेंशनर्स डे

75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनरों को किया सम्मानित

भोपाल। पेंशन भोगी स्वर्गीय श्री डी.एस. नाकारा के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बाई वी चंद्रचूड़ ने दिनांक 17 दिसंबर 1982 को दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को याद कर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर सैकड़ो पेंशनरों ने अंबेडकर पार्क में स्वर्गीय श्री डी एस नाकारा को कृतज्ञता के साथ याद किया ।

42 वां राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस के मुख्य अतिथि जस्टिस ए एन एस श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में सभी ऊर्जावान पेंशनरों को संगठित रहने का आह्वान किया एवं संगठन को भरपूर आर्थिक मदद करने की अपील की । कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पदाधिकारी संतोष ठाकुर ने किया । भोपाल के अध्यक्ष सुरेश शर्मा के नेतृत्व में किए गए आयोजन में पेंशनर हित में किया जा रहे प्रयासों एवं संगठन द्वारा दायर याचिकाओं पर सैकड़ो पेंशनरों ने संतोष व्यक्त किया एवं संगठन को हर संभव मदद करने का संकल्प लिया। आयोजन में संगठन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने 75 वर्ष एवं अधिक आयु के 50 पेंशनरों को शाल-श्रीफल देकर सम्मानित किया आमोद सक्सेना ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश पेंशनरों की लगातार उपेक्षा के कारण मजबूरी में उच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं दायर की गई है जिसके परिणाम पेंशनरों के हित में आएंगे संगठन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने उपस्थित पेंशनरों को सरकार की उपेक्षित नीतियों के विरुद्ध एकजुट होकर बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की । प्रमोद कुमार सिंघल, हरेंद्र तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष शंभू नाथ मुखर्जी, रामगोपाल माथुर, शैलेंद्र श्रीवास्तव एवं सलीम खान ने उपस्थित पेंशनरो का आभार व्यक्त किया बैरसिया के अध्यक्ष हरि बल्लभ शर्मा भेल के अध्यक्ष पी एन उपाध्याय, राजेंद्र नायक आर एस यादव, किशन सिंह यादव ने सभा को संबोधित किया।

स्विमिंग पूल और प्ले हाउस निर्माण के लिए भूमि पूजन सम्पन्न

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में, एम्स भोपाल ने अपने आवासीय क्षेत्र में स्विमिंग पूल और प्ले हाउस के निर्माण के लिए 17 दिसंबर 2024 को 'भूमि पूजन' किया। यह परियोजना एम्स भोपाल के आवासीय क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मनोरंजन और स्वास्थ्य-संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण

कदम है। इस अवसर पर उप निदेशक (प्रशासन) कर्नल (डॉ.) अजीत कुमार और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कर्नल चिरंजीव दास भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रो. सिंह ने कहा- स्वस्थ जीवनशैली के लिए खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। स्विमिंग पूल और प्ले हाउस जैसी सुविधाएं एम्स भोपाल के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए न केवल मनोरंजन बल्कि स्वास्थ्य और सामुदायिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देंगी। यह परियोजना संस्थान के आवासीय जीवन को और बेहतर बनाएगी।

भाजपा नेताओं द्वारा गुल्लक टीम के बच्चों के

दिवंगतों के प्रति प्रतिक्रिया मानवीय पतन और निष्क्रिष्टा का उदाहरण

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री मुकेश नायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेतागण आज मृतक मनोज-नेहा परमार के बच्चों से मुलाकात करने आष्ट पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने बच्चों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और ढांढ़स बंधाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की भारत जोड़ों यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी को अपनी पॉकिट मनी बचाकर गुल्लक भेंट करने वाले बच्चों को श्री नायक और श्री वर्मा ने पांच लाख रूपये की गुल्लक भेंटकर राहुल गांधी जी की भावनानुसार मित्रता का धर्म निभाया और उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर उनकी व्यवस्था करने का आश्वाशन दिया।

श्री नायक ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुये इस दुख की घड़ी में भी भाजपा के नेता अमानवीयता का परिचय देते हुए जिस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं वह मानवीय गरिमा के पतन और निष्क्रिटता का जीवंत उदाहरण हैं। ऐसे समय भाजपा के लोग इन बच्चों से मिलना तो दूर इन बच्चों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त नहीं की है जो भाजपाईयों की घृणता और नफरत, उसके चाल-चरित्र और चेहरे को प्रदर्शित करता है।

श्री वर्मा ने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप बच्चों को गुल्लक भेंट कर कांग्रेस ने अपने कर्तव्यों को निभाया है और बच्चों को इस संकट और दुख की घड़ी के समय अपना सार्मथ्य और संबल बनाये रखने साहस देंगे, उनकी शिक्षा-दीक्षा की जिम्मेदारी भी हम सभी मिलकर उठायेंगे। भाजपा का चरित्र मानवता की बजाय ढिढ़ोरा पीटना है, भाजपा के ठेकेदारों ने इन बच्चों को संवेदना तक नहीं दी, वह तो अपने स्वार्थ के लिए राजनैतिक स्वांग करती हैं।

इस मौके पर कांग्रेस नेतागण सर्वश्री शैलेन्द्र पटेल, कैलाश परमार, आशिफ जकी, राजीव गुजराती, बलवीर तोमर, देवेन्द्र पटेल, हरपाल सिंह, हरीश राठौर, विक्रम मस्ताल, फरजाना खान, सिद्धार्थ राजावत सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।

कांग्रेस ने स्वार्थ के लिए विधानसभाओं को भंग किया और बार-बार चुनाव कराने की प्रक्रिया में देश को उलझा दिया

वन नेशन, वन इलेक्शन आज देश की आवश्यकता : शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर कहा कि, हमारे देश में बार-बार, पांचों साल होने वाले चुनावों से देश की प्रगति और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सभी राजनैतिक दल, हमेशा चलने वाले चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। चुनावों के चलते प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और सभी जनप्रतिनिधियों का समय भी नष्ट होता है और भारी भरकम खर्च भी होता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, वन नेशन, वन इलेक्शन आज देश की आवश्यकता है। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, मैं वन नेशन, वन इलेक्शन बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि, आज वास्तव में समय आ गया है और जनता भी चाहती है कि, पांच साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो ताकि, साढ़े चार साल सभी राजनैतिक दल, देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करते रहें।

कांग्रेस ने संवैधानिक नियमों का उलंघ्घन किया- केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, आजादी के बाद वर्ष 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते रहे हैं, 1967 तक एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन अलग-अलग चुनाव करवाने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया। चुनी हुई सरकारें भंग कर दो और अलग-अलग चुनाव होने दो, कपड़ो की तरह सरकारें बदलती रही, और इसलिए चुनाव अलग-अलग समय पर हो गए। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए और अपने हितों को साधने के लिए एक के बाद एक विधानसभाओं को भंग करना शुरू कर दिया और देश को बार-बार चुनाव कराने की प्रक्रियाओं में उलझाकर रख दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, कांग्रेस हमेशा से ही संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती रही है। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो बार-बार आचार संहिता नहीं लगेगी और विकास कार्य निरंतर चलते रहेंगे।

बार-बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा- केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, हमारे देश में एक चीज़ लगातार चलती रहती है, पांचों साल बारह महीने अगले चुनाव की तैयारी। नवंबर में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए। चार महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए। वो चुनाव खत्म नहीं हुए कि, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव शुरू हो गए और अभी सांस भी नहीं ली कि, दिल्ली में उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है और बिहार चुनाव की तैयारियां हो रही है। ये बार-बार होने वाला चुनाव देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन गया है, ये विकास के लिए बाधा है। ये जनकल्याणकारी योजनाओं को रोकता है। सारे नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, केन्द्रीय मंत्री हों, राज्यों के मुख्यमंत्री हों, सांसद हो, विधायक हो, सभी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। जिन राज्यों में चुनाव नहीं होता, वहां भी दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता, नेता जाते हैं और केवल राजनेता और कार्यकर्ता ही नहीं जाते हैं, ऑब्जर्वर बनकर दूसरे प्रदेशों के अधिकारी भी वहां पहुंचते हैं।

समीक्षा नाटक

नारी की व्यथा कथा है नाटक ड्रमस्टिक

सक्सेना

भोपाल। रवीन्द्र भवन के अंजनी सभागार में 'ड्रमस्टिक' नाटक का मंचन हुआ । भोपाल की वरिष्ठ नाट्य संस्था 'भोपाल थियेटर्स' के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समां बांध दिया। दर्शकों से खचाखच भरे हॉल में उपस्थित हर दर्शक ने कड़ाके की ठंड में नाटक का भरपूर लुत्फ उठाया।

गजेंद्र अहिरे द्वारा मूल मराठी में लिखे गए नाटक 'शेवग्या चा शेंगा' का हिंदी अनुवाद रंगमंच के जानेमाने कलाकार प्रवीण महूवाले ने किया है। अभिनय की बारीकियों की समझ रखनेवाले प्रवीण महूवाले मराठी भाषी हैं । उनके द्वारा मराठी से हिंदी में किया गया भावानुवाद भाषा के स्तर पर नाटक में कहीं भी गतिरोध उत्पन्न नहीं करता है । प्रवीण के लिखे संवादों पर हॉल में दर्शकों की तालियां दर्शाती हैं कि अनुवाद की शैली पर उनकी कितनी मजबूत पकड़ है । प्रवीण से अपेक्षा है कि वे मराठी के अन्य अलक्षित नाटकों का हिंदी रूपान्तरण कर हिंदी रंगमंच को और समृद्ध करेंगे ।

'ड्रमस्टिक' यानी सेंजन की फली या मुनगे के पेड़ को रूपक के तौर पर लेकर ये नाटक लिखा गया है। ड्रमस्टिक का पेड़ जिसकी हर चीज फल, फूल, पत्ती सब कुछ तब तक उपयोगी है जब तक वो फलता फूलता रहता है । लेकिन पतझड़ के आते जब पेड़ अपनी आभा खो देता है तो हमारे लिए वो अनुपयोगी हो जाता है । उसे काट कर फेंक देने से भी हमें कोई गुरेज नहीं होता है। ठीक इसी तरह समाज में नारी की स्थिति है जब तक उसका सौंदर्य, कर्मशीलता, उसकी परिवार के लिए संघर्ष करने की क्षमता प्रबल रहती है, वो परिवार के केंद्र में होती है। वो धुरी होती है जिसके चारों ओर घर संसार घूमता है। पर जब उसका लावण्य, शारीरिक बल क्षीण होने लगता है, बेमुरव्वत, बेपरवाह पुरूष वादी समाज स्त्री का उपभोग कर उसे हाशिए पर डाल देता है ।

प्रसिद्ध रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता राजीव वर्मा ने इस नाटक का निर्देशन किया है । चार महिला पात्र नाटक के केंद्र में हैं । चारों की मनोदशा उनके जीवन की व्यथा को राजीव वर्मा के चुस्त निर्देशन ने मंच पर सजीव कर दिया है । मूल नाटक काफी लम्बा है । निर्देशक ने कुशलता से उसे एडिट करके कस दिया है । वे किसी दक्ष जुलाहे की तरह नाटक के हर पात्र को बारीकी से बुनते-रचते हैं। अपने निर्देशन से उसे ऊंचे मयार पर पहुंचा देते हैं। उनका श्रम पूरी प्रस्तुति में दिखता है। राजीव वर्मा को मंच पर अभिनय करते हुए देखना दर्शकों को हमेशा ही सुखकर लगता है । इस नाटक में भी वे सुधीर ससाने के रोल में सशक्त अभिनय से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं । रीता वर्मा अपने आला दर्जे के अभिनय और मंजी हुई देहभाषा से विमल बर्वे के चरित्र में जान डाल देती हैं। महुआ चटर्जी ने आरती के चुलबुले करेक्टर के पीछे छिपे दर्द को पूरी समझ और संवेदना के साथ बखूबी उजागर किया है ।

वाजपेयी के जन्म दिवस पर एम्स भोपाल का ग्वालियर में 3 दिवसीय चिकित्सा शिविर

ग्वालियर। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व और सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह की पहल पर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिवस के अवसर पर 3 दिवसीय मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। एम्स भोपाल के 160 डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की टीम इस विशेष शिविर में भाग लेंगी। कैंप में 25 अलग-अलग स्पेशलिटी और सुपर-स्पेशलिटी ओपीडी उपलब्ध होंगी, जहां हृदय रोग, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी, किडनी रोग, न्यूरोलॉजी, अस्थि रोग, बाल रोग, कैंसर, जनरल मेडिसिन सहित कई विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर चिकित्सा परामर्श, निदान और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

इस चिकित्सा शिविर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रो. सिंह ने कहा- यह मेगा मेडिकल कैंप श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत और ग्वालियर से उनके गहरे जुड़ाव को सम्मान देने का एक प्रयास है। इस पहल के माध्यम से हम चिकित्सा सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एम्स भोपाल यह सुनिश्चित करेगा कि कैंप में आने वाले मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर हमारे संस्थान में इलाज की निरंतरता मिले। इस कैंप की विशेषता यह है कि शिविर के दौरान उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों को एम्स भोपाल में इलाज के लिए के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें भविष्य में भी उचित और निरंतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। यह कैंप ग्वालियर और आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, जहां वे एम्स भोपाल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुफ्त में इलाज और परामर्श ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर के निधन पर ग्वालियर पहुंचकर परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में होगा खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 18 दिसम्बर को दोपहर 12:30 बजे तात्या टोपे खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व के उपलक्ष्य में 'खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह' होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग करेंगे।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिये यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में मंत्री श्री सारंग ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में खेल अधिकारियों के साथ समारोह पूर्व समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि समारोह गरिमापूर्ण एवं भव्य हो। समारोह में खिलाड़ियों को किट वितरण, श्रेष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान और खेल प्रोत्साहन की अन्य गतिविधियों को शामिल किया जाये। इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी, कोच एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल लोगों का सहयोग लिया जाये। कार्यक्रम की ब्रॉण्डिंग एवं बोर्डिंग की व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित हो।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि खेल छात्रवृत्ति में स्वर्ण जीतने वाले बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से चेक वितरण किया जाये। समारोह में खिलाड़ियों को किट वितरण, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि, प्रशिक्षण केन्द्र संचालन को प्रोत्साहन राशि आदि का वितरण भी सुनिश्चित हो। उपलब्धियों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी समारोह में किया जाये।

बैठक में संचालक श्री रवि कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक श्री बी.एल. यादव, उप सचिव श्री संजय जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कांग्रेस विधायक ने नामांकन में छिपाया 50 लाख का लोन

हाईकोर्ट ने माना सही ; आरिफ मसूद की विधायकी रहेगी या नहीं, 3 जनवरी को पता चलेगा

जबलपुर (नप्र)। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर विधानसभा चुनाव में भरे गए नामांकन पत्र में 50 लाख रुपए के लोन को छिपाने का आरोप है। सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी माना कि उन्होंने लोन की जानकारी छिपाई। जिसके बाद उनकी

विधायकी खतरे में है। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इस दिन पता चलेगा कि उनकी विधायकी रहेगी या नहीं।

दरअसल, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण की याचिका को निरस्त करने के लिए आवेदन लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और दावा किया कि जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर फिर से हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई के निर्देश दिए थे।

कोर्ट ने माना-लोन दस्तावेज सही

मंगलवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने ध्रुव नारायण की याचिका पर अंतिम तर्क सुनने के बाद माना कि एसबीआई बैंक, भोपाल से लोन के लिए पेश किए गए दस्तावेज सत्य और बैंक अधिकारी द्वारा अधिकृत हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि आरिफ मसूद ने चुनाव के दौरान इस लोन की जानकारी छिपाई थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरिफ मसूद द्वारा उठाई गई आपत्तियां पहले ही निर्धारित हो चुकी हैं, लिहाजा नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने बैंक से मांगी थी जानकारी

हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को 18 अक्टूबर तक लोन से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने एसबीआई शाखा प्रबंधक से कांग्रेस विधायक और उनकी पत्नी के लोन की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान बैंक मैनेजर ने भी स्वीकार किया कि लोन के जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, वे सत्य हैं और बैंक के अभिलेखों के अनुरूप हैं। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा के साथ एडवोकेट पंखुड़ी विश्वकर्मा भी मौजूद थीं।

वकील बोले- आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में

याचिकाकर्ता के वकील, सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा, ने बताया कि कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के आवेदन और सभी आपत्तियों को निरस्त कर दिया है। यदि अंतिम सुनवाई में यह सिद्ध हो जाता है कि आरिफ मसूद और उनकी पत्नी ने बहुत बड़ी राशि का लोन लिया और चुनाव के दौरान इसकी जानकारी छिपाई, तो वे भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाएंगे। ऐसे में उनकी विधायकी खत्म हो सकती है।

भर गया महाकाल का खजाना साल भर में 112 करोड़ रुपए से अधिक की आय

शीघ्र दर्शन टिकट और भस्म आरती बुकिंग से आय बढ़ी

उज्जैन (नप्र)। भक्तों की भेंट से भगवान महाकाल का खजाना फिर भर गया है। 1 जनवरी से 13 दिसंबर 2024 तक मंदिर समिति को विभिन्न स्त्रोतों से 112 करोड़ 31 लाख 85 हजार 988 रुपये की आय हुई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, वर्ष 2024 में शीघ्र दर्शन टिकट व भस्म आरती बुकिंग से आय बढ़ी है। अन्नक्षेत्र में भी गतवर्ष

की तुलना में अधिक दान आया है। विविध आय भी दो गुना हो गई है। अभी दिसंबर माह के 18 दिन शेष है। इस अवधि में जो भी आय होगी, इसे मिलाकर इस साल की आय पिछले साल से अधिक रहेगी।

लड्डू प्रसाद की बिक्री से प्राप्त राशि शामिल नहीं

मंदिर प्रशासन के आय के आंकड़े जारी किए हैं। इस राशि में लड्डू प्रसाद की बिक्री से प्राप्त राशि शामिल नहीं है, क्योंकि लड्डू प्रसाद लागत मूल्य पर विक्रय किया जाता है। इसलिए यह आय नहीं है।

1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक मंदिर समिति को 14 करोड़ 58 लाख 4 हजार 675 रुपये की आय हुई थी। वहीं वर्ष 2024 में 1 जनवरी से 13 दिसंबर तक 112 करोड़ 31 लाख 85 हजार 988 रुपये प्राप्त हुए हैं।

मोहन सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश, आज चर्चा

कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, घेराव करने निकले सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका

भोपाल (नप्र)। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज के विरोध में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक हाथों में कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही मंगलवार को विधानसभा में सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस पर बुधवार को 4 घंटे चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक हाथों में कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

महिला सुरक्षा, किसान समस्या और बेरोजगारी को लेकर भोपाल में समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। विधानसभा घेरने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिंक रोड नंबर एक पर मयूर पार्क के पास रोक लिया। यहां बैरिकेडिंग की गई थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने कहा- हम जेल जाएंगे।

उन्होंने कहा- बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर फेल है। किसान परेशान हैं। एमएसपी नहीं मिल रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम इस सरकार को उखाड़ फेकेंगे। आज यहां से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इसके बाद हर जिले में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज के विरोध में कांग्रेस के विधायक हाथों में कटोरा लेकर विधानसभा पहुंचे। यहां गांधी प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि बीजेपी सरकार प्रदेशवासियों पर कर्ज का बोझ लादती जा रही है। प्रदेश के लोगों की स्थिति कटोरा लेकर भीख मांगने जैसी होने लगी है।

विधानसभा में शुरुआती 7 सवाल महिला विधायकों ने किए- विधानसभा के भीतर प्रश्नोत्तर काल से कार्यवाही शुरू हुई। इसमें महिला सशक्तिकरण के नाम पर शुरुआती 7 सवाल महिला विधायकों ने किए। पहला सवाल सीधी विधायक रीति पाठक ने किया। उन्होंने सीधी विधानसभा में दो पुलिस चौकियां खोलने की मांग की। इस पर गृहमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से जवाब देने के लिए अधिकृत राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने यह कहकर चौकी खोलने की अनुमति को अमान्य कर दिया कि इसके नियमों में पेंच है।

तराना विधायक बोले- म.प्र.में दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला- तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा- मध्यप्रदेश में दिल्ली से कई गुना बड़े शराब घोटाले को अंजाम दिया गया है। ये 10000 करोड़ का घोटाला है। 2015-16 में जो एफडीआई घोटाला इंदौर में हुआ था, मैंने उसको लेकर ध्यान आकर्षण लगाया था। उसके जवाब में आबकारी विभाग ने स्वीकार किया कि 71 करोड़ का घोटाला हुआ है।

अकेले इंदौर में 71 करोड़ का घोटाला हो गया तो पूरे मध्यप्रदेश में हजारों करोड़ों का घोटाला होगा। अब तो ईडी-सीबीआई दोनों इसकी जांच कर रहे हैं। 6-7 साल से मामले की जांच चल रही है और दोषी अधिकारी खुलेआम घूम रहे हैं। इसमें तात्कालिक मंत्री शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जेल भेजा जाना चाहिए।

कुलपति का नाम कुलगुरु करने का विरोध, पीएम पर टिप्पणी- विधानसभा में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधायक 2024 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कुलपति का नाम कुलगुरु करने का विरोध किया। इस दौरान पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया और सत्ता पक्ष तथा कांग्रेस के विधायक तेज आवाज में बहस करने लगे।

मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी कांग्रेस के सीनियर नेताओं को लेकर टिप्पणी की। जब शोर शराबा नहीं थमा तो अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि, एक तरफ हम आचरण की बात करते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर उमंग सिंघार ने कहा कि, मंत्री जी को भी अपने शब्द वापस लेना चाहिए।

मंत्री बोले- एमपीपीएससी को 1736 पदों के लिए डिमांड भेजी गई

मंत्री परमार ने कहा कि, विश्वविद्यालय सिर्फ अपनी परीक्षाएं आयोजित करते हैं। पीएससी या अन्य किसी परीक्षा से विश्वविद्यालय का मतलब नहीं होता है। मंत्री ने बताया कि, 1736 पदों के लिए डिमांड पीएससी को भेजी गई है। मंत्री के प्रस्ताव के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सभी सदस्यों की सहमति से मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक 2024 को पारित घोषित किया।

शारदा मंदिर का कंट्रोल अब मैहर कलेक्टर के पास होगा

विधानसभा में इसके साथ ही 22460 करोड़ 18 लाख 6 हजार 621 रुपए का सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस पर बुधवार को 4 घंटे चर्चा होगी। इसके बाद अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश किया गया। सदस्यों से चर्चा के बाद विधेयक पारित हुआ।वहीं, मां शारदा देवी मंदिर संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इस संशोधन विधेयक में मंदिर के अध्यक्ष सतना कलेक्टर की जगह मैहर कलेक्टर होंगे।

17 साल की पोती ने की दादा की हत्या

प्रेम-प्रसंग को लेकर चचेरी बहन से किया विवाद ; रोकने पहुंचे तो मारा था पत्थर

मऊगंज (नप्र) मऊगंज में नाबालिग पोती ने अपने ही 79 साल के दादा की हत्या की थी। इसका खुलासा पोस्टमॉर्ट्म रिपोर्ट में हुआ। चचेरी बहन ने लड़की के प्रेम-प्रसंग की शिकायत की, तो वह लड़ने लगी। दादा बीच-बचाव करने आए तो पोती ने पत्थर उठाकर उनके सीने पर मार दिया। क्योंकि शरीर से खून नहीं निकला था, इसलिए पुलिस ने मामले को संदिग्ध बताया था।

पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारी चीज मारने से शरीर के

अंदरुनी पार्ट डैमेज हो गए थे। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर आरोपी पोती को गिरफ्तार कर लिया।

मामला 3 दिसंबर का है। 7 दिसंबर को अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हुई। 13 दिसंबर को पीएम रिपोर्ट मिलने पर हत्या का केस दर्ज किया गया। 14 दिसंबर को आरोपी पोती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से बालिका संप्रेक्षण बंदी गृह शहडोल भेज दिया गया है। राम कृपाल कुशवाहा की रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 7 दिसंबर को मौत हो गई थी।

सीने में उठा था दर्द, अस्पताल में मौत

झौरा गांव निवासी राम कृपाल कुशवाहा (79) के सीने में 7 दिसंबर को तेज दर्द उठा। गंभीर हालत में उन्हें मऊगंज सिविल अस्पताल लाया गया था। चोट ज्यादा होने से डॉक्टरों ने संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया। यहां इसी दिन रात में मौत हो गई। पुलिस ने 8 दिसंबर की दोपहर 12 बजे पीएम के बाद शव परिजन को सौंप दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी थी।

घर पर लड़के आने से हुआ विवाद

रामकृपाल कुशवाहा की पोती ने बताया, 3 दिसंबर की बात है। मैंने ताऊजी को बोला- कि उनके घर में कुछ लड़के आते हैं, तो मेरे घर की तरफ से निकलते हैं। इसी बात पर शाम को ताऊजी की बेटी ने गाली-गलौज की थी। जैसे-तैसे मामला शांत हो गया। सुबह करीब 11 बजे फिर वह गाली-गलौज करने लगी। मैंने पिता को कॉल करके बताया। साढ़े 11 बजे फिर लड़ाई हो गई। उसके पिताजी मुझे ही भला-बुरा कहने लगे। कुछ देर बाद सड़क पर फिर लड़ने आ गई। मेरे साथ मारपीट की। इस बीच, दादाजी राम कृपाल कुशवाह बीच-बचाव करने आ गए। इतने में चचेरी बहन ने पत्थर लेकर दादाजी के सीने में मार दिया। इसके बाद वह चली गई। परिजन ने पोती पर शक जताया था, लेकिन सबूत के अभाव में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पूछताछ में भी लड़की ने कुछ नहीं बताया। शरीर से खून भी नहीं निकला था। इस कारण पुलिस असमंजस में थी।

जांच के बाद हत्या का केस दर्ज

पुलिस अधीक्षक मऊगंज रसना ठाकुर ने बताया कि कुछ दिन पहले देवतालाब में घटना हुई थी, जिसमें दो बहनें आपस में झगड़ा कर रही थी। झगड़े में ही उनके दादा बीच-बचाव करने जब आए, तो उन्हें धक्का दे दिया। जिससे वे नीचे गिर गए। गिरने के बाद भी दोनों एक दूसरे पर पत्थर चला रहे थे। इसी बीच एक पत्थर दादा (मृतक) को लग गया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। वो रीवा हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां डेथ हो गई। जांच पड़ताल और पीएम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया।

हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में एमपी हाईकोर्ट का फैसला

परिजन को 15-15 लाख मुआवजा

जबलपुर/हरदा (नप्र)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वाले लोगों के परिजन को 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये आदेश केवल मृत्यु के मामलों में मुआवजा के लिए हैं। प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता फैक्ट्री मालिकों को यह छूट दी है कि वे घायलों, संपत्ति नुकसान और अन्य मदों के लिए तय मुआवजे को लेकर एनजीटी में आपत्ति उठा सकते हैं। कोर्ट ने एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) को कहा है कि सभी बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद अंतिम आदेश जारी करें।

एनजीटी ने घटना के दिन ही आदेश पारित किया- 6 फरवरी 2024 को हरदा की पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा करीब 60 मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। एनजीटी ने घटना के दिन ही आदेश पारित किया कि मृतकों के परिजन और घायलों को मुआवजा बांटा जाए। एनजीटी ने प्रशासन को आदेश दिया था कि फैक्ट्री मालिकों की संपत्ति की नीलामी कर मुआवजे की राशि जुटाएं।

फैक्ट्री मालिक ने आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती- एनजीटी के इस आदेश को फैक्ट्री मालिक सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने दलील दी कि जिस दिन घटना हुई, उसी दिन एनजीटी ने आदेश दे दिया। जबकि घटना के दिन घायलों और संपत्ति नुकसान का आंकलन भी नहीं हुआ था। उन्होंने दलील दी कि कई लोग गलत तरीके से मुआवजे का दावा कर रहे हैं।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता को घायलों-पीड़ितों के वर्गीकरण, संपत्ति और मकानों के नुकसान, विस्थापन के लिए दी जाने वाली राशि के वर्गीकरण के संबंध में आपत्ति उठाने का अधिकार होगा। आपत्ति पर सुनवाई के बाद एनजीटी कानून के अनुसार उस पर विचार कर अपना आदेश सुनाएगी।

ग्वालियर में केन्द्रीय विद्यालय के दो टीचरों पर एफआईआर

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में केंद्रीय विद्यालय के 9वीं के एक छात्र ने स्कूल से घर लौटकर फिनाइल पीकर सुसाइड का प्रयास किया था। गंभीर हालत में परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। छात्र की जान बच गई थी। घटना 8 नवंबर 2024 की है।

अब इस मामले में पुलिस ने केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2 के दो टीचर रश्मि गुप्ता व दिवाकर शर्मा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों शिक्षक छात्र को प्रताड़ित करते थे उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे। जिससे आहत छात्र ने यह कदम उठाया था। अब पुलिस दोनों शिक्षकों को इस मामले में गिरफ्तार करेगी। छात्र के बैग से यह पत्र मिला मिला था, जिसमें उसने दो टीचरों के द्वारा परेशान किए जाने की बात लिखी थी।

पिता घर लौटे तो बेटे को उल्टियां करते देखा- 14 साल का पीड़ित छात्र ग्वालियर के डीडी नगर का रहने वाला है। वह भिंड रोड पर स्थित केंद्रीय विद्यालय-2 में 9वीं में पढ़ता है।

8 नवंबर की सुबह वह स्कूल गया था। वहां से घर लौटा तो टॉयलेट में रखी फिनाइल पी ली। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। दोपहर में पिता घर पहुंचे तो बेटे को उल्टियां करते हुए देखा।

बेटे की हालत बिगड़ती देख उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती कराया। वहां उसके फिनाइल पीने का पता लगा था। समय पर अस्पताल पहुंचाने के चलते छात्र की जान बच गई थी। छात्र की कॉपी से परिजन को एक सुसाइड नोट मिला था। जिसने सभी को चौका दिया था।

फिनाइल पीने से पहले छात्र ने लिखा था नोट

छात्र ने स्कूल की कॉपी में लिखा था कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूं। मुझे मेरी मैम रश्मि गुप्ता और दिवाकर सर परेशान और टॉर्चर करते हैं। रश्मि मैम मुझे परीक्षा में फेल करने की धमकी देती हैं। मैं इनसे परेशान होकर यह कदम उठा रहा हूं। मेरे इस कदम के जिम्मेदार रश्मि मैम और दिवाकर सर रहेंगे।

मां बोलीं थी- दोनों टीचर फेल करने की धमकी देते थे

छात्र की मां ने बताया था कि बेटे की क्लास टीचर रश्मि गुप्ता और दिवाकर शर्मा सर उसे दिमागी रूप से टॉर्चर कर रहे थे। उसे लगातार परेशान कर रहे थे। मेरे बेटे ने इन टीचरों की प्रताड़ना के कारण फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दोनों शिक्षक उसे बार-बार टॉर्चर कर रहे थे कि वे उसे 9वीं से 10वीं क्लास में नहीं जाने देंगे।